● वर्ष-4
● अंक-94
रायपुर, गुरुवार
28 नवंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» करियर की अपार संभावनाएं होटल..

बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग

नई दिल्ली। बांग्लादेशी सरकार ने बुधवार को इस्कॉन या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन कहा, जो संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका के जवाब में था। यह घटनाक्रम हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों द्वारा इस्कॉन और अन्य हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने को लेकर पूरे बांग्लादेश में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ है।

बुधवार को एक वकील ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। वकील ने अदालत का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया कि सहायक सरकारी अभियोजक सैफुल इस्लाम की सुरक्षा कर्मियों और हिंदू भिक्षु के अनुयायियों के बीच झड़प के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान, अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन के बारे में और बांग्लादेश में इसकी स्थापना

कैसे हुई, इसके बारे में जानना चाहा।

जवाब में, अटॉर्नी जनरल, मोहम्मद असदुज्जमां ने कहा कि यह संगठन कोई राजनीतिक दल नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है। सरकार पहले से ही उनकी जांच कर रही है।

उच्च न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि वे इस्कॉन पर सरकार की स्थिति और देश की समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति पर गुरुवार सुबह तक रिपोर्ट दें। न्यायालय ने सरकार से कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने को कहा।

विशेष रूप से, कुछ सप्ताह पहले अटॉर्नी जनरल ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने का सुझाव दिया था, क्योंकि देश की 90% आबादी मुस्लिम है।

याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने विश्व नेताओं से इस मुद्दे पर बोलने का आग्रह किया और उम्मीद जताई कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण के बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी।

दास ने इंडिया टुडे से कहा, स्थिति नियंत्रण से बाहर है। अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम 20 जनवरी का इंतजार करेंगे जब डोनाल्ड ट्रम्प पदभार संभालेंगे। उम्मीद है कि तब चीजें आगे बढ़ेंगी। इस्कॉन नेता ने अटॉर्नी जनरल द्वारा कट्टरपंथी संगठन कहे जाने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में बाढ़ के दौरान भी हमने बहुत से लोगों की सेवा की। हमसे पूछा गया कि हमने ऐसा क्यों किया, फिर भी हमने ऐसा किया। इस्कॉन ने दुनिया भर में आठ अरब लोगों को खाना खिलाया है। और हमें एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है?

फडणवीस का सीएम बनना तय!

मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर कई दिनों से चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए कार्यवाहक-सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और खुद को सीएम की दौड़ से बाहर कर दिया। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। उन्होंने प्रचंड जीत के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो किसी भी पद या स्थिति के लिए परेशान होंगे। उन्होंने सीएम पद छोड़ने का बड़ा संकेत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए जो भी फैसला करेंगे, वह उससे सहमत होंगे। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि हमारी महायुति में कभी भी एक-दूसरे के प्रति मतभेद नहीं रहा। हमने हमेशा एक साथ बैठकर निर्णय लिया है और हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम चुनाव के बाद (सीएम पद के संबंध में) सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को संदेह है जिसे एकनाथ शिंदे जी ने आज स्पष्ट कर दिया है। जल्द ही हम अपने नेताओं से मिलेंगे और फैसला लेंगे।

एकनाथ शिंदे ने खुद को दौड़ से किया बाहर

महायुति ने चुनावों में भारी जीत हासिल की और 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटें हासिल कीं। उन्होंने कहा कि मैं न तो परेशान हूं, न ही नाराज हूं। पिछले दो-चार दिनों से आपने ऐसी अफवाहें देखी होंगी कि कोई नाराज है। हम नाराज़ होने वाले लोग नहीं हैं। मैंने कल प्रधानमंत्री से बात की और उन्हें बताया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में हमारी ओर से कोई बाधा नहीं है। आप निर्णय लें। बीजेपी का फैसला अंतिम है। एनडीए का नेता कौन है? पीएम मोदी और एचएम अमित शाह। इसलिए मैंने उन दोनों को फोन किया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आप निर्णय लें और हम निर्णय स्वीकार करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीएम पद को लेकर जो भी फैसला लेंगे, उनके उम्मीदवार को शिवसेना पूरा समर्थन देगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को भारी जीत दिलाने के बाद, मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के लिए सोमवार देर रात राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद महाराष्ट्र में भाजपा की कायापलट का श्रेय जाने वाले देवेन्द्र फडणवीस पहले ही भाजपा आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार के भी राजधानी के लिए रवाना होने की संभावना है।

महायुति में कभी मतभेद नहीं रहा-देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री किस दल का होगा। इसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए तय कि राज्य की शीर्ष दल भाजपा के शीर्ष नेता जो भी फैसला लेंगे और जिस किसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएंगे। उस उम्मीदवार को शिवसेना पूरी तरह से समर्थन देगी। वहीं उनके इस बयान पर भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमारी महायुति में कभी भी एक-दूसरे के प्रति मतभेद नहीं रहा। हमने हमेशा मिल-बैठकर निर्णय लिए हैं और चुनाव से पहले हमने कहा था कि चुनाव के बाद हम (मुख्यमंत्री पद के बारे में) सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे। कुछ लोगों को संदेह है, जिसे आज एकनाथ शिंदे जी ने स्पष्ट कर दिया है। जल्द ही हम अपने नेताओं से मिलेंगे और निर्णय लेंगे। जबकि राज्य के नए कैबिनेट को लेकर किए गए सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कि महाराष्ट्र के अगले कैबिनेट को लेकर फैसला अगले मुख्यमंत्री की तरफ से उनके नाम पर अंतिम मुहर लगने के बाद लिया जाएगा।

अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा!

अजमेर। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हिंदू शिव मंदिर होने के दावे का वाद बुधवार को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए पक्षकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वादी विष्णु गुप्ता ने विभिन्न साक्ष्य के आधार पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा पेश किया था।

बता दें कि मामले में कल यानी मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। आज भी न्यायालय में

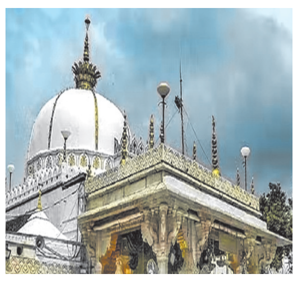

सुनवाई हुई और न्यायालय ने वाद को स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण धरोहर को नोटिस जारी करने के आदेश जारी करने का फैसला दिया है। वादी विष्णु गुप्ता की ओर से हरदयाल शारदा की ओर से लिखी पुस्तक का हवाला देते हुए वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को की जाएगी।

हिंदू पक्ष का दावा...

- दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था
- मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था
- याचिका में अजमेर निवासी हर विलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी पुस्तक का हवाला
- पुस्तक में दरगाह के स्थान पर मंदिर का जिक्र
- दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश

अदालत ने स्वीकार की हिंदू पक्ष की याचिका

तहखाने में गर्भगृह होने का प्रमाण

बताते चलें, इससे पहले हिंदू सेना की तरफ से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका पेश की गई थी। हालांकि, न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने ये कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया था कि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद जिला अदालत में याचिका पेश की गई।

न्योता

राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों के पंथी नर्तक दल हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता बेमेतरा जिले के विकासखण्ड मुख्यालय नवागढ़ में 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में सतनामी समाज प्रमुखों के दल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से उनके निवास कार्यालय में भेंट कर उन्हें प्रतियोगिता में शामिल होने का न्योता दिया।

प्रमुख समाचार

महिला जजों की बर्खास्तगी: तीन को विचार करेगा सुको

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त की गई दो महिला सिविल जजों के खिलाफ एक सीलबंद रिपोर्ट पर तीन दिसंबर को विचार करेगा। इस रिपोर्ट में कथित तौर पर उनके असंतोषजनक प्रदर्शन और अन्य कारणों का विवरण है। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को इस मामले का संज्ञान लिया था, जब राज्य सरकार ने छह महिला जजों को उनकी कथित असंतोषजनक कार्यप्रणाली के कारण बर्खास्त कर दिया था। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 23 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को यह आदेश दिया था कि वह जजों की बर्खास्तगी पर फिर से विचार करे। इसके बाद, 1 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्ण अदालत ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और चार जजों को कुछ शर्तों को फिर से बहाल करने का फैसला लिया। ये चार जज ज्योति वर्गड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर जोशी थीं। हालांकि, सरिता चौधरी और अदिति कुमार शर्मा के मामले में पहले के आदेशों को रद्द नहीं किया गया और हाईकोर्ट ने इन दोनों जजों के खिलाफ जानकारी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीलबंद रिपोर्ट के रूप में रखने का फैसला लिया।

जनता ने कांग्रेस पार्टी को किनारे कर दिया है- संबित

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी सांसद संबित पात्रा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाने को लेकर बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को किनारे कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल (26 नवंबर को) संविधान दिवस था। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस कार्यालय में श्वङ्करूको कोसा है और कहा कि हमें श्वङ्करूहटाना है और बैलेट पेपर को फिर से लेकर आना है। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए पात्रा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप ईव्हीएम हटाओ या न हटाओ, लेकिन जनता ने कांग्रेस को साइड में रख दिया है। करीब हर राज्य के चुनाव में कांग्रेस साइड लाइन कर दी गई है। महाराष्ट्र में तो नेस्तनाबूद हो गई है। उन्होंने कहा कि एक ओर महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हुई है तो वहीं कांग्रेस का सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि हर राज्य के चुनाव में कांग्रेस को किनारे कर दिया गया है, यहां तक कि झारखंड में भी। आज कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का सफाया हो गया है।

पाकिस्तान सरकार के टॉर्चर के आगे झुके इमरान के समर्थक

इस्लामाबाद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक, जो क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे थे, इस्लामाबाद में अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि सुरक्षाकर्मियों ने आधी रात को उनके प्रदर्शन पर कार्रवाई शुरू कर दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान खान के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं, जिसमें छह सुरक्षाकर्मी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। पाकिस्तानी टीवी चैनलों ने खान के समर्थकों को आंसू गैस का सामना करते हुए और डी-चौक की ओर जाने वाली सड़कों पर रखे शिपिंग कंटेनरों पर चढ़ते हुए फुटेज दिखाए, जो कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों - प्रेसीडेंसी, पीएम कार्यालय, संसद और सुप्रीम कोर्ट के करीब स्थित है। पाकिस्तान में विपक्षी समर्थकों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों को अस्थायी रूप से वापस ले लिया है। इससे एक दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद के मध्य में मार्च किया था। प्रदर्शनकारियों ने खान की रिहाई तक राजधानी नहीं छोड़ने की कसम खाई थी।

झारखंड में 'अबुआ सरकार' की नयी पारी आज से

रामगढ़ (झारखंड)। झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद बृहस्पतिवार से 'अबुआ सरकार' (हमारी सरकार) की नयी पारी शुरू होगी। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले सोरेन अपनी पत्नी कल्पना के साथ अपने दादा सोबरन सोरेन को उनकी 67वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ जिले में अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, ''मैं अपने दादा सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि देने हर साल इस स्थान पर आता हूं।'' सोरेन ने अपने गांव वालों को रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले अपनी सरकार के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। नेमरा के लुकैयाटांड में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के गठन का काम जारी है। सोरेन ने ग्रामीणों से कहा, ''कल से 'अबुआ सरकार' (हमारी सरकार) की नयी पारी शुरू होगी। शपथग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को होना है। मैं आप सभी को इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी ने अबुआ सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए बहुत मेहनत की है।''

संभल हिंसा: भाजपा समर्थकों की भी जारी करें तस्वीरें

लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को संभल हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की कीमत वसूलने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उसे कथित तौर पर नारे लगाने वाले भाजपा समर्थकों की तस्वीरें भी जारी करनी चाहिए। संभल में रविवार को मुगलकालीन मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई। एक स्थानीय अदालत ने एक याचिका के जवाब में सर्वेक्षण का आदेश दिया था जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के विनाश के बाद किया गया था। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने (भाजपा) अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता है और इसलिए उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए (संभल में) यह दंगा कराया है। अगर सरकार तस्वीरें जारी कर रही है तो उन्हें उन बीजेपी समर्थकों की तस्वीरें भी जारी करनी चाहिए जो सर्वे के दौरान वहां मौजूद थे और नारे लगाए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान नहीं बल्कि मन विधान के आधार पर चलती है।

संसद में वक्फ बिल पर बने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर आम सहमति लिए बनाई गई (जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी) की बैठक में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ. जेपीएस की 8वीं बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी. विपक्षी दलों ने 29 नवंबर को ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश करने के चेयरमैन के फैसले पर असहमति जाहिर की. हंगामे के बीच विपक्षी दलों के सदस्यों ने जेपीएस के एक्सटेंशन की मांग करते हुए मीटिंग का बहिष्कार कर दिया. विपक्षी नेता यह तर्क देते हुए जेपीएस की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए कि आगे कोई कदम उठाने से पहले जेपीएस के एक्सटेंशन पर विचार किया जाना चाहिए. इसके बाद चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने जेपीएस का कार्यकाल बढ़ाने की बात कही. इसे लेकर गुरुवार में लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, जेपीएस का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस हिसाब से साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा. वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीएस की बैठक का बहिष्कार करने वाले विपक्षी सदस्यों का कहना है कि कमिटी ने सभी राज्यों की बात नहीं सुनी है. संसदीय समिति में शामिल विपक्षी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर पैनल के चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल पर विपक्ष की राय लिए बिना एकतरफा निर्णय लेने का आरोप लगा चुके हैं.

जेपीएस का बहिष्कार करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा- लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संकेत दिया था कि कमिटी का एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन चेयरमैन ने 29 नवंबर को ही ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश करने का फैसला ले लिया. ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा मंत्री जगदंबिका पाल की कार्रवाई

को डायरेक्ट कर रहा है.

इस बीच भाजपा में शामिल विपक्षी सांसदों के बहिष्कार के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पैनल के विस्तार की मांग की. उन्होंने बजट सेशन तक एक्सटेंशन मांगा है.

बिल पर क्या है विवाद?

वक्फ का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अल्लाह के लिए दे देना, जिसके बाद उस चीज पर उस इंसान और उसके परिवार का हक नहीं होता है. इस वक्त करीब 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर है. इसमें वो भी जमीन शामिल हैं, जिन्?हें छोड़कर आजादी के वक्त मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे. साथ ही नवाबों और राजाओं आदि द्वारा इस्लाम के लिए जमीन को वक?फ किया गया है. इन जमीनों पर लखनऊ का ऐशबाग ईदगाह, बड़ा इमामबाड़ा समेत कई बड़ी मस्जिदें, कब्रिस्तान आदि बने हुए हैं. मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती, वो लोग भी ज्यादातर अपनी जमीन को वक्फ के नाम कर जाते हैं. जिसके बाद उस जमीन पर मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान आदि बन सके और वो इंसानों के काम आ सके.

वक्फ की जमीन पर स्कूल और अस्पताल भी बना सकते हैं, जिसमें हर कौम का इंसान अपना इलाज करा सकता है और पढ़ाई कर सकता है यानी वक्फ की जमीन से हर इंसान को फायदा पहुंच सकता है. भारत सरकार के अनुसार, देश में वक्फ की जमीन करीब 9.4 लाख एकड़ में है, जिसकी कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये है. इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन भारत में है. भारत में रेलवे और आर्मी के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की जमीन है, जिसे वक्फ बोर्ड संभालता है.

वक्फ बोर्ड को लेकर मंत्रालय ने डेटा जारी किया है, जिसमें कहा है कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली में 566 शिकायतें वक्फ बोर्ड की मिली हैं, जिसमें से 194 शिकायतें अवैध रूप से वक्फ भूमि के अतिक्रमण और स्थानांतरण के संबंध में हैं और 93 शिकायतें मुतावल्ली या वक्फ बोर्ड सदस्यों के खिलाफ है.

मुतावल्ली वो शख्स होते हैं, जिन्?हें वक्फ की संपत्ति की देखभाल के लिए अपाइंट किया जाता है. वहीं मंत्रालय ने ट्रिब?यूनल कोर्ट की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया और पाया कि ट्रिब?यूनल कोर्ट में में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ प्रबंधित संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं.

बिल को लेकर क्या विवाद है?

बीते दिनों संसद में एक नया विधेयक लाया गया, जो 1995 के वक्फ कानून की जगह लेगा. इसे लेकर विवाद हुआ. इसके बाद सरकार ने इस बिल को 8 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया. इससे पहले, लोकसभा में इसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था.

गोद ग्राम में विकास के दावों की खुली पोल

झांकने तक नहीं आते सीमेंट कंपनी के अधिकारी और सरकारी अमला

आक्रोशित महिलाओं ने कहा- गांव में है पानी की बड़ी समस्या

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार भाटापारा जिला सीमेंट का हब है और यहां की बेशकीमती धरती का सीना चीरकर पत्थर रूपी रत्न निकाल अरबों खरबों रुपए कमाने वाली कंपनियां अपने ही गोद ग्राम के विकास, साफ-सफाई सहित अन्य विकास के कार्यों पर ध्यान नहीं दे रही है। ताजा मामला न्यूवेको सीमेंट संयंत्र सोनाडीह के गोद ग्राम खपरी का है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई समस्याएं हैं। शासन-प्रशासन के साथ ही सीमेंट कंपनी के अधिकारी झांकने तक नहीं आते हैं।

गांव की महिलाओं का कहना है कि शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीण महिलाएं समस्याओं से जूझ रही है। ग्रामीण महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जहां कंपनी के खदान की अत्यधिक खुदाई से पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। यह समस्या गर्मी के दिनों में और भी विकराल हो जाती है, जिसे लेकर न्यूवेको कंपनी के प्रति

ग्रामीणों में रोश व्याप्त है।

ग्राम पंचायत मेढ़ के आश्रित ग्राम खपरी की ग्रामीण महिला गौरी धुव ने बताया कि यहां पर सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। गर्मी के पहले तालाब, डबरी सूख गए हैं। हमें निस्तारी के लिए लगभग दो किमी नदी जाना पड़ता है। वहीं सीमेंट कंपनी वाले अधिकारी कभी नहीं आते हैं, जबकि यह गोद ग्राम है। यहां हम लोगों को कपनी कोई सुविधा नहीं देती है। गर्मी के दिनों में तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। सरपंच-सचिव भी ध्यान नहीं देते हैं। काफी तकलीफ होती है।

ग्रामीणों को योजनाओं तक की जानकारी नहीं

ग्राम की बुजुर्ग महिला मुनित बाई ने बताया कि कंपनी शुरुआत में यहां आती थी। स्वास्थ्य जांच होता था पर अब लोग नहीं आते हैं। हम लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। नल जल योजना भी यहां नहीं है। सरपंच-सचिव बाहर रहते हैं इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होती है। शासन द्वारा चावल मिल रहा है बाकी कोई योजना की जानकारी नहीं है और न ही लाभ मिल रहा।

दूसरे गांव के हैं सरपंच-सचिव कलेक्टर बोले- जांच कराता हूं

ग्रामीण महिलाओं का यह भी आरोप है कि सरपंच-सचिव दूसरे गांव के हैं इसलिए यहां आते नहीं है और आते है तो पता नहीं चलता। हमें अपने काम के लिए उनके घर जाना पड़ता है। पानी को लेकर सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को होती है, क्योंकि उन्हें घर संभालना पड़ता है। महतारी वंदन योजना का भी लाभ पूरे महिलाओं को नहीं मिला है, कमाने खाने गए थे। इस तरह देखे तो न्यूवेको सीमेंट कंपनी सोनाडीह द्वारा अपने गोद ग्राम में विकास को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि आपके माध्यम से ग्राम खपरी की जानकारी मिली है, मैं जांच करवाता हूं।

टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा कसडोल शहर में पकड़ा गया बाघ, सीएम साय ने फॉरेस्ट विभाग को दी बधाई

बलौदाबाजार। कसडोल शहर के नजदीक पहुंचे बाघ को वन विभाग ने सफलतापूर्वक काबू पा लिया। कसडोल शहर से लगे ग्राम कोट में धान के पैरे के एक ढेर में बाघ छिपा हुआ था। वन विभाग की टीम पहुंची और बेहद कुशलता से बाघ को ट्रैक्यूलाइज किया। ट्रैक्यूलाइज करने के बाद बाघ कुछ देर तक होश में रहा और पास ही के पेट्रोल पंप के पीछे की तरफ भाग गया। लेकिन कुछ ही देर में बाघ बेहोश हो गया और फिर वन विभाग की टीम ने उस पर नियंत्रण पा लिया।

संभावना जताई जा रही है कि बाघ ओडिशा के रास्ते बारनवापारा अभयारण्य पहुंचा होगा। आठ महीने से यह बारनवापारा में ही सक्रिय था। बाघ की सक्रियता केवल कोर एरिया में रहे इसके लिए वन विभाग ने पर्याप्त प्रयास किये। लेकिन जब बाघ का मूवमेंट कोर एरिया से बाहर होने की खबर मिली तो वन अमले ने सतर्कता से अपनी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि अब बाघ को किसी टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा ताकि इसे और भी सुरक्षित परिवेश मिले।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाघ को रेडियो कॉलर लगा दिया गया है। इससे बाघ के मूवमेंट पर नजर रखने में आसानी होगी। इसके खून का नमूना भी लिया गया है। बाघ पूरी तरह स्वस्थ है। बता दें कि बाघ के शहर के पास होने की सूचना मिलते ही वन विभाग एवं वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी कानन पेण्डारी चिड़ियाघर बिलासपुर डॉ. पी के। चंदन वन्यप्राणी चिकित्सा अधिकारी नंदन वन

जू एवं जंगल सफारी नवा रायपुर डॉ. राकेश वर्मा और डॉ. रश्मिलता राकेश पशु चिकित्सा अधिकारी कसडोल की टीम तुरंत कोट गांव पहुंची। ग्रामीण धीराजी के बाड़ी में रखे पैरा के ढेर में छुपे बाघ को ट्रैक्यूलाइज किया।

सीएम साय ने वन विभाग की टीम को दी बधाई

सीएम विष्णुदेव साय ने वन विभाग के अधिकारियों को बाघ के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बधाई दी है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टायगर रिजर्व के रूप में एक नया टायगर रिजर्व मिल गया है। जो आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व के बनने से बाघों को नैचुरल हैबिटेट में बेहतर परिवेश मिल पाएगा और इनके बेहतर संवर्धन के अवसर मिलेंगे।

अनियंत्रित मेटाडोर ने चार लोगों को मारी टक्कर

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

दुर्ग। दुर्ग में छावनी थाना क्षेत्र में एक मेटाडोर अनियंत्रित हो गई और राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया और छावनी सीएसपी कार्यालय परिसर के गेट क्षतिग्रस्त कर रुकी। इस घटना में 4 लोगो घायल हो गए सभी घायलों को सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से एक घायल को दुर्ग जिला अस्पताल रेफर किया गया पुलिस वाहन को जप्त कर और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पूरा मामला पावर हाउस पुराना ओवर ब्रिज का है जहां भिलाई टाउनशीप से नंदिनी रोड की तरफ मेटाडोर जा रहा था इस दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों और दुकान को टक्कर मारते हुए राहगीर आईटीआई के तीन छात्राएं और फेरी लगाने वाले दुकानदार एक बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया और छावनी सीएसपी कार्यालय के गेट को क्षतिग्रस्त कर रुकी स्थानीय लोगो ने घटना की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद 4 घायलों को सुपेला अस्पताल ले जाया गया जहां से एक घायल को दुर्ग जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद पुलिस ने मेटाडोर वाहन को जप्त कर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि एक मेटाडोर अनियंत्रित होकर आईटीआई के छात्राएं और फेरी लगाने वाले एक बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए सीएसपी कार्यालय के गेट क्षतिग्रस्त करते हुए नुकसान पहुंचा है पुलिस ने सभी घायलों को सुपेला जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जहां एक की बेहतर इलाज के लिए दुर्ग जिला अस्पताल रेफर किया गया है मेटाडोर क्रमांक छग 07 ह्र 5692 भिलाई टाउनशीप से नंदिनी रोड की तरफ जा रहा था इस दौरान अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।

मॉर्निंग वॉक पर निकली तीन महिलाओं को कंटेनर ने मारी टक्कर, एक मौत और दो गंभीर

जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में तेज रफ्तार छोटा कंटेनर वाहन के चालक ने मॉर्निंग वॉक पर निकले तीन महिलाओं को पीछे से जोरदार ठोकर मारी है। हादसे में 30 वर्षीय महिला लक्ष्मी भारद्वाज की मौत हुई है। वहीं दो महिलाएं गम्भीर रूप से घायल हुई है जिनका उपचार जिला अस्पताल जांजगीर में जारी है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। दरअसल,, बुधवार की सुबह करीबन 6.30 बजे लक्ष्मी भारद्वाज, ज्योति यादव और सुनीता बरेठ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। पुलिस लाईन के पास सड़क में पैदल चल रहे थे। इस दौरान डाक पार्सल लिखा तेज रफ्तार छोटा कंटेनर वाहन पीछे से आकर तीनो महिलाओं को अपनी चपेट में लेते हुए जोरदार ठोकर मारी हादसे में तीनो एक दूसरे से दूर जा गिरी, वहीं लक्ष्मी भारद्वाज के सिर पर गंभीर चोट आने से मौके पैर ही मौत हुई। ज्योति यादव और सुनीता बरेठ को गंभीर हालत में जिला अस्पताल जांजगीर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि पुलिस लाईन में पदस्थ आरक्षक प्रवीण भारद्वाज की पत्नी लक्ष्मी भारद्वाज की मौत हुई है। छोटा कंटेनर वाहन और चालक को पकड़ा लिया गया है। थाने में अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

भाजपा नेता और सरकारी कर्मचारी हुए आमने-सामने

एक ने काम नहीं करने, तो दूसरे ने काम नहीं करने देने का आरोप लगाते हुए धरना पर बैठे

कलेक्टर को करना पड़ा बीच-बचाव

महासमुंद। ऐसा वाकया आपने न कभी सुना होगा, न कभी देखा होगा। बुधवार को महासमुंद तहसील कार्यालय में जैसा वाकया हुआ, उससे परिसर में मौजूद लोग अवाक रह गए। एक तरह भाजपा प्रवक्ता व उनके समर्थक तो दूसरी तरफ तहसील कार्यालय के कर्मचारी एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए एक ही परिसर में धरने पर बैठ गए। आखिरकार कलेक्टर को बीच-बचाव कर मामला शांत कराना पड़ा।

दरअसल, भाजपा प्रवक्ता डॉ. विमल चोपड़ा बुधवार को महासमुंद तहसील परिसर में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। डॉ. चोपड़ा ने आरोप लगाया कि पिछले 7-8 माह से छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर किसान, कामगार, गरीब और तमाम लोग तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर के पास आ रहे हैं, पर कोई काम नहीं हो रहा है। तहसील में बिना पैसा दिए कोई कार्य नहीं होता है। जनता प्रताड़ित है, इसीलिए आज यहां धरने पर बैठे है। एक सप्ताह में कार्य नहीं होता है तो हम लोग राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे।

दूसरी तरफ तहसील कार्यालय के कर्मचारी भी डॉ विमल चोपड़ा पर न्यायालीन कार्य नहीं करने देने का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। तहसील कर्मचारियों ने कहना था कि हम लोग पिछले दो-तीन महीनों से परेशान हैं। डॉ. विमल चोपड़ा न्यायालीन एवं कार्यालयीन कार्यों में दखलअंदाजी करके दवाब डालते हैं, इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल कर धरने पर बैठे हैं। धरने से बनी स्थिति को देखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने दोनों पक्षों से बातचीत कर समस्या का समाधान जल्द निकालने की बात कही।

जहां गूंजती थी गोलियों की गूंज अब वहां मोबाइल में बजेगी घंटी

बीजापुर। सरकार के कामकाजों से बस्तर की तस्वीरें लगातार बदल रही है। जहां पहले गोलियों की आवाज गूंजती थी वहां अब लोग सुकून से रह रहे हैं। नियद नेल्ला नार योजना के तहत छूटवाई गांव में मोबाइल टावर की सुविधा शुरू की गई है। इससे अब बीजापुर जिले के सुदूर ग्राम छूटवाई, गुंडेम, कोंडापाल्ली, गगनपल्ली, मुरकिनार के ग्रामीणों को संचार सुविधा का लाभ मिलेगा।

इस नई पहल से अब ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क का लाभ मिलना संभव हो गया है। साथ ही मजबूत नेटवर्क एवं इंटरनेट की सुविधा से ग्रामीण अंचल के पढ़ने वाले छात्रों एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को ऑनलाइन पढ़ाई में लाभ मिलेगा।

सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम से क्षेत्र में अब संचार की सुविधा बहाल हो चुकी है। स्थानीय निवासियों को अब आसानी से अपने परिवार के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे उनके दैनिक जीवन में सहजता आई है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नवागढ़ में होगी राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता

बेमेतरा। परम पूज्य गुरुघासी दास बाबा की जयंती के उपलक्ष्य में अगले माह दिसंबर में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन बेमेतरा जिले के नवागढ़ में होगा। नवागढ़ विधायक व प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में गुरू घासीदास जयंती व राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता को आपसी प्रेम और सौहाद्रपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। पहले भी राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन नवागढ़ में किया जा चुका है, इस पंथी नृत्य को देखने छत्तीसगढ़ से ही नहीं देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं। मंत्री श्री बघेल ने राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि यह प्रतियोगिता तीन दिनों तक आयोजित की जाएगी। अभी से प्रदेश के पंथी नृत्यक दलों को आमंत्रण देने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। बैठक में प्रतियोगिता का स्वरूप, आयोजन समिति, सुरक्षा समिति सहित अन्य व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रमों में समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ-साथ अन्य समाज के प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान करना चाहिए।

दलपत सागर में 7 दिसम्बर को किया जायेगा दीपोत्सव

जगदलपुर। दलपत सागर में प्रति वर्ष की भाँति 7 दिसम्बर को दीपोत्सव किया जायेगा। इस दीपोत्सव के सफल आयोजन हेतु कलेक्टर श्री

हरिस एस ने शहर के समाजसेवी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, सर्व समाज प्रमुखों, युवोदय की टीम और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील की है कि तैयारी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग करें। इस दीपोत्सव में लगभग तीन लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किया जाएगा। इसके लिए दीपों, तेल और बाती की व्यवस्था हेतु कलेक्शन सेंटर, पार्किंग व्यवस्था, दलपत सागर परिसर में कार्यक्रम उपरांत सफाई सहित अन्य व्यवस्था में सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। दीपों का संग्रहण हेतु सभी एसएलआरएम सेंटर और दलपत सागर को चिन्हांकित किया गया जहां पर नागरिक स्वेच्छा से दीप, तेल, बाती आदि प्रदान कर सकते हैं।

सड़क हादसे में पिता को खोने के बाद लोगों को किया जागरुक

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के जरवाही में रहने वाले युवक बीरेंद्र साहू ने 2022 में पिता को एक सड़क हादसे में खोने के बाद पूरा परिवार लोगों को हेलमेट बांटने का काम कर रहे हैं। अब तक युवक ने निशुल्क 1000 से अधिक हेलमेट लोगों को बांट चुका है। डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम जरवाही गांव में रहने वाले बीरेंद्र साहू की सगाई डोंगरगांव ब्लॉक के करियाटोला की ज्योति साहू के साथ हुई। सगाई रस्म के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को पहले अंगूठी पहनाई फिर हेलमेट पहनकर सुरक्षा को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। सगाई समारोह में यह दृश्य देखकर कुछ देर के लिए मेहमान भी चौंक गए, बीरेंद्र के पिता पंचराम साहू काम के बाद बाइक से घर लौट रहे थे हेलमेट नहीं पहने थे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनके सिर में गंभीर चोट आई। जनवरी 2022 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद बीरेंद्र ने परिवार के साथ लोगों को जागरुक किया। सड़क हादसे में पिता को खोने के बाद बीरेंद्र ने ठाना की अब लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करूंगा।

श्री सीमेंट फैक्ट्री के सेलो में मिली मजदूर की लाश

बलौदाबाजार। खपराडीह स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री के सेलो में बुधवार को मध्यप्रदेश के ग्राम चंदवार में रहने वाले मजदूर की लाश मिलने से यहां कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। मजदूरों की सूचना मिली सुहेला पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मजदूर अशोक सिंह पिता गुलाब सिंह (33 वर्ष) मध्यप्रदेश के चचाई थाना क्षेत्र के ग्राम चंदवार का रहने वाला है और वह श्री सीमेंट फैक्ट्री के नए प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। रोजाना की तरह वह कल भी काम पर गया था लेकिन रात में घर नहीं लौटा। परिजन उसकी रात भर खोजबीन व तलाश कर रहे थे कि बुधवार की सुबह सुबह सेलो में उसकी लाश मिलने से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तत्काल सुहेला पुलिस के साथ परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

छत्तीसगढ़ में मालगाड़ी डिरेल होने के बाद रूट क्लियर नहीं

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के बिलासपुर कटनी रेल रूट पर मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। भनवारटंक रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के कोयले से भरे 22 डिब्बे डिरेल हो गए। मालगाड़ी के डिरेल हुए डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए। इस हादसे के चलते अप और डाउन दोनों मार्ग बाधित हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के आलाधिकारी सहित तकनीकी टीम भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किए। इस हादसे की वजह से मंगलवार को ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ। बुधवार को भी कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। हादसे के बाद जंगल के बीच हुए इस हादसे का ड्रोन से लिया गया वीडियो भी सामने आया है। 27 नवंबर को गाड़ी संख्या 08740 बिलासपुर-शहडोल, 27 नवंबर को गाड़ी संख्या 08739 शहडोल-बिलासपुर मेमू रद्द रहेगी। 27 नवंबर को गाड़ी संख्या 08747/बिलासपुर-कटनी मेमू शहडोल स्टेशन से प्रारम्भ होगी और गाड़ी संख्या 08748 कटनी-बिलासपुर मेमू शहडोल स्टेशन में समाप्त होगी।

व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश

सूझबूझ से बचा व्यापारी, केस दर्ज

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के केदारपुर इलाके में रहने वाले युवा व्यापारी के साथ डिजिटल ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि, व्यापारी की सतर्कता के चलते वह साइबर ठगों के झांसे में नहीं आया। शिवेश ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

युवा व्यापारी शिवेश सिंह को व्हाट्सएप के जरिए एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए आरोप लगाया कि शिवेश के नंबर से कई लोगों को आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए हैं। कार्रवाई का डर दिखाते हुए, ठग ने व्यापारी को एक कमरे में बंद होने के निर्देश दिए।

इसके बाद, कॉलर ने शिवेश से आधार नंबर और पैन कार्ड की जानकारी मांगी। लेकिन, व्यापारी की सतर्कता और जागरूकता ने उसे ठगी का शिकार होने से बचा लिया। शिवेश ने कॉल पर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की और कॉल काट दी।

शिवेश ने इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ठग किस तरह मानसिक दबाव बनाकर डिजिटल तरीके से अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे।

सरगुजा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ने बताया कि व्यापारी की शिकायत के बाद वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस तरह के साइबर ठग पीड़ित को मानसिक दबाव में डालकर उनकी गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं और ठगी को अंजाम देते हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने लोगों को इस प्रकार के कॉल से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस तरह की घटना का सामना करना पड़े, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। डिजिटल अरेस्ट के मामलों में ठग फोन कॉल या मैसेज के जरिए दबाव बनाते हैं। किसी भी संदिग्ध कॉल पर अपनी गोपनीय जानकारी साझा न करें और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट तुरंत साइबर क्राइम शाखा को दें।

एसीबी ने रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी/ईओडब्ल्यू की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बुधवार को फिर बलरामपुर जिले के राजपुर ब्लॉक के ओकरा पथलपारा में

पदस्थ पटवारी को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुताबिक, फौती नामांतरण के एवज में पटवारी ने पैसे की मांग की थी। लंबे समय से पटवारी पैसे के लिए आवेदक पर दबाव बना रहा था। इसकी शिकायत पर एसीबी की टीम ने पटवारी पवन पाण्डेय को 12 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

फॉरेस्ट गार्ड की हाईटेक भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट जारी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मॉनिटरिंग

कबीरधाम। वन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न वनमंडल में वनरक्षक (फॉरेस्ट गार्ड) के 1 हजार 484 रिक्त पद पर सीधी भर्ती किया जा रहा है। कवर्धा वनमंडल अंतर्गत वनरक्षक के 65 पद पर भर्ती प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 8 दिसंबर तक चलेगी।

बुधवार 27 नवंबर को फिजिकल टेस्ट हुई। भर्ती में किसी प्रकार की गड़बड़ी या धांधली ना हो, इसके लिए शारीरिक माप-जोख व दक्षता परीक्षा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किया जा रहा है। लंबाई व सीना माप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से होने के बाद अभ्यर्थियों को बारकोड युक्त चेस्ट जारी कर उनके पैर में गैजेट लगाया जाता है।

इस गैजेट का उपयोग 200 व 800 मीटर दौड़ में किया जा रहा है, जिसका सटीक आंकड़ा तुरंत डिवाइस के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। दौड़ के बाद गोला फेंक, लंबी कूद परीक्षा में भी इलेक्ट्रॉनिक

डिवाइस का उपयोग किया जा रहा। इसमें भी तुरंत सटीक आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं।

डीएफओ शशि कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही। अभी तक भर्ती के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कवर्धा वनमंडल में वनरक्षक के रिक्त 65 पद के लिए कुल 29 हजार 892 आवेदन प्राप्त हुए है। अभ्यर्थियों के लिए नींबू, पानी, फर्स्ट एड बॉक्स, चिकित्सा व अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल ने नक्सली हिंसा में घायल जवानों को ईलाज के लिए आर्थिक सहायता दी

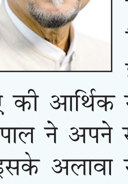

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए नक्सली हिंसा में घायल हुए कांकेर जिले के जिला रिजर्व फोर्स के दो जवानों श्री खिलेश्वर गावड़े और श्री हिरामन यादव को बेहतर ईलाज के लिए 25-25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता। प्रदान की यह राशि राज्यपाल ने अपने स्वेच्छानुदान मद से प्रदान की है। इसके अलावा सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर संचालनालय सैनिक कल्याण बोर्ड को 2 लाख रूपए की राशि भी स्वेच्छानुदान मद से प्रदान की है। उन्होंने आम जनता से भी 7 दिसम्बर को मनाए जाने वाले सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के उपलक्ष्य में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक राशि देने की अपील की।

राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी

रायपुर। सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सीजीपीएससी में विभिन्न विभागों में बंपर भर्ती निकली है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें आबकारी उप निरीक्षक के सबसे अधिक 90 पद हैं। डिप्टी कलेक्टर के 7 पद हैं। इस बार डीएसपी के लिए 21 पद शामिल हैं। प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 01 से 30 दिसंबर तक भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत उम्मीदवार 31 दिसंबर से दो जनवरी 2025 तक अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी को दो पालियों आयोजित की जाएगी। पहला सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगा। मुख्य परीक्षा 26, 27, 28 और 29 जून 2025 को आयोजित की जाएगी।

राज्यपाल से अपना घर आश्रम रायपुर के अध्यक्ष ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से बुधवार को यहां राजभवन में अपना घर आश्रम रायपुर (गोढ़ी) के अध्यक्ष श्री गोपाल प्रसाद सुल्तानिया एवं अन्य पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने आश्रम में 2 दिसंबर को होने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने हेतु राज्यपाल को आमंत्रित किया। इस अवसर पर श्री साइमन अग्रवाल, श्री नागपाल, श्री गोपाल अग्रवाल, श्री संदीप केडिया, श्री विजीत अग्रवाल उपस्थित थे।

राज्यपाल डेका ने पहलरू बहुमूल्य जीवन बचाने की पुस्तक का किया विमोचन

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने बुधवार

को राजभवन में पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के निश्चेतना विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. प्रतिभा जैन शाह द्वारा लिखित पहलरू बहुमूल्य जीवन बचाने की पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में आपातकालीन स्थिति में जीवन बचाने के लिए उपचारों के संबंध में जानकारी दी गई है। हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित इस पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने को कहा।

हाई कोर्ट की पुख्ता की जा रही सुरक्षा

बिलासपुर। उच्च न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। इस लिहाज से कोर्ट के अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा अधिवक्ताओं, सहायकों और परिसर में कार्यरत अन्य शासकीय विभागों के कर्मियों के लिए क्यूआर कोड/बार कोड मय फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था बनाई जा रही है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में शासकीय कर्मचारी-अधिकारियों के अलावा अधिवक्ताओं और सुरक्षा कर्मियों से पहचान पत्र बनवाकर, संबंधित जानकारी कोर्ट में आने-जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन की जानकारी एडिशनल रजिस्ट्रार कार्यालय में 15 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध कराने कहा गया है।

व्यापारिक संघों को आईडीबीआई करेंसी चेस्ट ने वितरित किया करेंसी नोट व चिल्हर

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को दोपहर 1.00 बजे चेम्बर कार्यालय, चै.देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में आईडीबीआई बैंक पचपेड़ीनाका, रायपुर शाखा के द्वारा चेम्बर से संबद्ध एसोसियेशन- रायपुर प्लायवुड टेऊडर्स एसोसियेशन, रायपुर मशीनरी मर्चेन्ट एसोसियेशन, डुमरतराई व्यापारी कल्याण महासंघ एवं रायपुर स्वीट एंड स्नैक्स एसोसियेशन को 1, 2, 5, 10 एवं 20 के सिक्के तथा 20, 50 एवं 100 रूपये के करेंसी नोट का वितरण किया गया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम पर उठाया सवाल

कहा- लोस चुनाव में जिस बूथ से हम जीते, वहां विस चुनाव में एक वोट नहीं मिला!, यह कैसे संभव

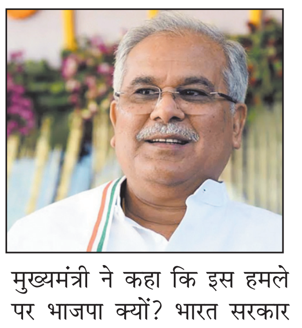

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जिस पोलिंग बूथ से हम जीते थे, आज वहां एक भी वोट नहीं मिल रहा है, ये कैसे संभव है? आदमी जुड़े घटाए और ग़लत हो जाए तो समझ आता है। लेकिन मशीन का जोड़ना-घटाना ग़लत हो जा रहा है, ये कैसे संभव है?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। इस दौरान ईवीएम को लेकर किए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते थे, तो शाम-रात तक मतदान का प्रतिशत पता चल जाता था। लेकिन आज ईवीएम में दूसरे दिन तक आंकड़े बदलते रहते हैं। इसका अंतर थोड़ा बहुत नहीं लाखों-करोड़ों में होता है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हमले पर भाजपा क्यों? भारत सरकार को आवाज उठाना चाहिए न, भारत सरकार का सोई हुई है। दुनिया में कहीं भी भारतीय हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसकी जिम्मेदारी विश्व गुरु की है, हर जगह भाजपा राजनीति न करे। घड़ियाली आँसू न बहाए। भारत सरकार को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से बात कर सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये शर्मनाक बात हैं, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए।

छत्तीसगढ़ सरकार के गुड गवर्नेंस पर भूपेश बघेल ने कहा कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में हत्याएं, लूट, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएँ हो रही हैं। लेकिन सरकार गुड गवर्नेंस की बात करती है। शिक्षक अपनी छात्रा के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ऐसी सरकार से भगवान बचाए।

वहीं कवर्धा में फर्जी मतदाता पर कहा कि बृजमोहन अग्रवाल सहित सारे लोग घुसपैठियों की बात करते थे। सालभर हो गया सरकार बने, कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किए सरकार बताएं।

कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आगामी 29 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। बैठक में कोई ठोस निर्णय होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सविधान दिवस के अवसर पर खड़गे के वक्तव्य से लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा समेत अन्य राज्यो में हमारे मुताबिक निर्णय नहीं आया है, लेकिन हम इसका आकलन करेंगे।

हार पर कांग्रेस का ईवीएम राग, लखमा ने बैलेट से चुनाव की मांग की

बस्तर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महाविकास अघाड़ी की करारी हार हुई। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से कांग्रेस के आला नेताओं ने ईवीएम से चुनाव कराने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस के इस सियासी सुर का समर्थन कोंटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने किया है। कवासी लखमा ने कहा है कि अगर आने वाले समय में बैलेट से चुनाव नहीं होते हैं तो वे ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे।

कवासी लखमा ने कहा कि देश में ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव कराए जाने चाहिए। केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के लोग भी बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। कवासी लखमा ने दावा किया कि लोग कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया लेकिन मशीन अलग ही चल रही है। ऐसी स्थिति जब अमेरिका जैसे देश में बैलेट से चुनाव हो रहे हैं तो भारत में बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो सकता।

कवासी लखमा ने कहा विश्व के बड़े बड़े देशों में शुमार अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में भी बैलेट से चुनाव हुआ। उस दौरान जीत हार में वोटों का अंतर इतना देखने को नहीं मिला। आज के चुनावों में जीत हार में वोटों का अंतर ज्यादा दिखता है। महाराष्ट्र का चुनाव इसका उदाहरण है।आने वाले समय में बैलेट से चुनाव होने चाहिए। हम इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

कवासी लखमा ने बस्तर के शहीद कर्मा यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने फीस वसूली का प्रमाण 21 नवम्बर को थमा दिया। यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ने से कोंटा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, किरंदुल और बस्तर के कॉलेजों में प्रभाव पड़ेगा। फीस निर्धारण के लिए जल्द से जल्द बोर्ड के गठन की मांग कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने की है।

कवासी लखमा ने कहा बस्तर यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ने से बस्तर के आदिवासी गरीब जो गरीबी की स्थिती में पढ़ाई करते हैं। उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। यह बोझ डालने का काम विष्णुदेव की सरकार सांय सांय कर रही है। इसीलिए कांग्रेस मांग करती है कि बोर्ड का गठन जल्दी हो। 21 नवंबर को जारी हुए फीस वृद्धि के आदेश को समाप्त किया जाए।

कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने छत्तीसगढ़ के वन विभाग में भर्ती का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वनरक्षक की 1000 भर्तियां स्वागत के योग्य है। कवासी लखमा ने इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी प्राइवेट कंपनी से भर्ती कराई जा रही है। जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। क्योंकि आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा

■ गृहमंत्री विजय शर्मा ने धमकी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज को जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को डॉ. सलीम राज को मिल रही धमकियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को धमकी मिली है, क्योकि उन्होने स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने के लिए ऐसे मदरसों में जहां धार्मिक की जगह राजनीतिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं, उन्हें रोकने का प्रयास किया था। गृहमंत्री शर्मा ने कहा की उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। स्पष्टता के साथ वह काम करें, सरकार उनके साथ है।

बता दें कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने हाल ही में मस्जिदों के मुतवल्लियों को निर्देश जारी किया था। निर्देश के मुताबिक मस्जिदों में होने वाली तकरीर की जानकारी मुतवल्ली अब वक्फ बोर्ड को देंगे। वक्फ बोर्ड का फरमान जारी होने के बाद सलीम राज को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि छह इंच छोटा और सिर कलम करने की भी धमकी मिली है।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, मैं मस्जिदों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दूंगा और धमकी से डरने वाला भी नहीं हूं। मैंने जो नियम बनाया है वह देशहित के लिए और सर्वहित के लिए है। इस नियम में साफ है कि तकरीर के दौरान राजनीतिक भाषण न हो, जिससे सामाजिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। हमारे निर्णय के बाद 154 मुतवल्ली ने टॉपिक भेजा था जिसे हमने अप्रूव कर दिया है। जो वक्फ बोर्ड का अवगत नहीं कराएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

जिला सहकारी बैंक में करोड़ों का घोटाला एनएसयूआई ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

■ कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की दी चेतावनी

रायपुर। जिला सहकारी बैंक में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर एनएसयूआई ने कलेक्टर गौरव कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर एनएसयूआई ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान एनएसयूआई जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी समेत सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने बताया कि सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर प्रदेश का सबसे बड़ी और पुरानी वित्तीय संस्था है, जहां लाखों किसानों के करोड़ों रुपए शेयर के रूप में जमा है। बीते सालों में बैंक के अधिकारियों द्वारा ही करोड़ों रुपए का गबन किया है। बैंक कर्मी ही जब बैंक को लुटेंगे तो बाहरी चोर और डकैतों की जरूरत ही नहीं है।

प्रशांत ने बताया, बैंक के सीओडी शाखा में बीते सालों में दस करोड़ से अधिक का गबन हुआ है। पिछले साल सितंबर 2023 में हमारे पार्टी के नेता और बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष पंकज शर्मा के निर्देशों पर कुछ अधिकारियों के खिलाफ मौदहापारा पुलिस थाने में अपराध दर्ज कराया गया था। अब भाजपा सरकार आने पर घोटालेबाज अधिकारी और कर्मचारियों को बचाया जा रहा है। इस घोटाले में बैंक में 20 से ज्यादा कर्मचारी सीधे तौर पर शामिल हैं, जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। किसी भी कर्मचारी को अब तक निलंबित भी नहीं किया गया है

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बताया, कर्मचारी नेता मोहनलाल साहू के खाते में 20 लाख से अधिक रकम जमा हुआ है फिर भी कार्रवाई नहीं की गई है। बैंक प्रबंधन द्वारा जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। मीडिया मे लगातार बैंक में गबन संबंधी खबरें प्रकाशित हो रही है। उसके बाद भी घोटालेबाजों पर बैंक प्रबंधन कार्रवाई नही कर पा रहा है। दोषी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर अपराध दर्ज कराएं। एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर बैंक मुख्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की होगी।

ग्रीन एनर्जी हेतु एन.टी.पी.सी. व छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी में करार

■ मुख्यमंत्री साय ने इसे नये युग की शुरुआत बताया

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के डंगनिया, रायपुर स्थित मुख्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी तथा एन.टी.पी.सी. की सहायक कंपनी मेसर्स एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया जिसके अनुसार ये दोनों कंपनियां मिलकर एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाएंगी। संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से राज्य में लगभग 2 गीगावॉट (2 हजार मेगावॉट) क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास का काम करेंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस करार को छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नये युग की शुरूआत बताया। प्रदेश के ऊर्जा सचिव तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने कहा कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से काम करते हुए एक नया इतिहास रचेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड तथा नेशनल थर्मल पॉवर कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एन.जी.ई.एल.) के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के प्रबंध निदेशक श्री एस.के. कटियार तथा एन.टी.पी.सी. के रीजनल एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर श्री पी.के. मिश्रा की उपस्थिति में एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन में एन.जी.ई.एल. की ओर से महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी) श्री धीरेंद्र जोशी और सी.एस.पी.जी.सी.एल. की ओर से मुख्य अभियंता (कार्पोरेट प्लानिंग एण्ड बिजनेस डेवलपमेंट) श्री गिरीश गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया। ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का संपादन किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन, राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वों (आर.जी.ओ.) के पालन में सहायक सिद्ध होगा तथा जिसके द्वारा हरित ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस करार से राज्य में हरित ऊर्जा स्त्रोतों से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, जिससे कि राज्य की भावी विद्युत आवश्यकताओं के साथ ही राज्य के समग्र विकास और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के ई.डी. सी.एल. नेताम, एम.आर. बागड़े, संदीप मोदी, मुख्य अभियंतागण जे.एस. बोंडे, रजनीश जांगड़े, एम.एस. कंवर, रोहित डहरवाल, संजय शुक्ला, मनीष गुप्ता, अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्र, विभागीय अभियंता अतनु मुखोपाध्याय, आशुतोष शुक्ला, नीरज वर्मा सहित एन.टी.पी.सी. के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में पहली बार एमएमआई नारायणा अस्पताल में अचेत मरीज की सफल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी

रायपुर। एमएमआई नारायणा हेल्थ अस्पताल रायपुर ने छत्तीसगढ़ में पहली बार जागते हुए मरीज की क्रैनियोटोमी और न्यूरोमॉनिटरिंग तकनीक का उपयोग करते हुए ब्रेन ट्यूमर हटाने की सफलतापूर्वक सर्जरी की। यह उन्नत प्रक्रिया 25 वर्षीय मरीज के लिए नई उम्मीद लेकर आई। साथ ही अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्टता को दर्शाती है।

इस सर्जरी का नेतृत्व डॉ. घनश्याम ससापारधी ने किया, जो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में विशेषज्ञ हैं। मरीज को बार- बार दौरे पड़ रहे थे और मस्तिष्क के उस हिस्से में ट्यूमर पाया गया था जो बोलने और शरीर के दाहिने हिस्से की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ट्यूमर की संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने जागते हुए क्रैनियोटोमी करने का निर्णय लिया।

इस प्रक्रिया के दौरान मरीज को स्थानीय एनेस्थीसिया देकर पूरी तरह चेतना में रखा गया। ऑपरेशन के दौरा डॉक्टर मरीज से बात करते रहे और अपने शरीर के भागो में गतिविधि करने के लिए कहते रहे, जिससे वास्तविक समय में मरीज के मस्तिष्क की गतिविधियों में निगरानी करने में मदद मिलती है। न्यूरोमॉनिटरिंग तकनीक ने सर्जरी को अत्यधिक सटीक और सुरक्षित बनाया, जिससे स्वस्थ मस्तिष्क संरचना को किसी भी क्षति से बचाया जा सका। इस तकनीक से मरीज को लकवा होने का खतरा नहीं रहता है एवं मरीज का मनोबल बना रहता है और रिकवरी भी जल्दी होती है। ब्रेन ट्यूमर की इस एडवांस तकनीक से राज्य के मरीजों को हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े शहरो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

डॉ. घनश्याम ससापारधी ने इस उपलब्धि पर कहा, हमें गर्व है कि हम अपने मरीजों को बिना बेहोश किये क्रैनियोटोमी सर्जरी किया है। यह तकनीक हमें ट्यूमर को पूरी तरह हटाने में मदद करती है और मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य, जैसे बोलना, याददाश्त और गतिविधियों को सुरक्षित रखने का अवसर देती है। सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार आया और सर्जरी के तीसरे दिन अस्पताल से स्वस्थ होकर छुट्टी ले ली। इस सफलता में डॉ. एचपी सिन्हा (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. राकेश चंद, डॉ. धर्मेश कुमार लाड (एनेस्थीसियोलॉजिस्ट) और टीम, और डॉ। प्रदीप शर्मा (क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ) और टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

एमएमआई नारायणा हेल्थ अस्पताल रायपुर के फैसिलिटी डायरेक्टर अजित बेलमकोंडा ने कहा, यह सर्जरी हमारी मेडिकल टीम की उत्कृष्टता और उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। हमारा लक्ष्य नवीनतम तकनीक और सहानुभूतिपूर्ण देखभाल के साथ मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। इस ऐतिहासिक सर्जरी के साथ एमएम आई नारायणा हेल्थ अस्पताल रायपुर ने मरीज-केंद्रित और उन्नत चिकित्सा सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। अस्पताल आधुनिक तकनीक और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिससे मरीजों को जीवन में नई उम्मीदें मिल रही है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग राजनांदगांव (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण)

निविदा विज्ञप्ति क्र. 7466 /15/ नि.वि./ लोनिवि / 2024-2025 दिनांक 25/11/2024

छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किये गये 'ई' श्रेणी पंजीयन में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा प्रपत्र AE में प्रतिशत दर पर ब्लाक स्तर पर निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 17/12/2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक
2. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 30/12/2024 अपरान्ह 5.30 बजे तक
3. निविदा खोलने की तिथि : 31/12/2024 अपरान्ह 11.30 बजे

क्रमांक .	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	अमानती राशि
01	02	03	04
	सीमेंट कांक्रीट पहुंच मार्ग का निर्माण (विकासखंड – राजनांदगांव)		
1	ग्राम मगरलोटा से आंगनबाड़ी तक 130 मीटर	8.71	6600.00
2	ग्राम बुचीभरदा अरला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक 115 मीटर	7.10	5500.00
3	ग्राम सिंघोला में पशु चिकित्सालय भवन तक 200 मीटर	11.69	8800.00
4	ग्राम आलीखुटा (रानीतराई) में श्मशान घाट तक 200 मीटर	11.69	8800.00
5	ग्राम रवेली में श्मशान घाट तक 100 मीटर	7.05	5300.00
6	ग्राम भोथीपार में श्मशान घाट तक 100 मीटर	7.05	5300.00
7	ग्राम कुसमी पारीखुर्द में औद्योगिक क्षेत्र तक 100 मीटर	7.05	5300.00
8	ग्राम पंचायत पारीखुर्द में आवास पारा से गौठान तक लंबाई 300 मीटर	18.99	14300.00
9	मुख्य मार्ग से आवास पारा से शासकीय माध्यमिक शाला पारीखुर्द पहुंच मार्ग लंबाई 250 मीटर	15.95	12000.00
10	ग्राम पंचायत पारीखुर्द में आवासपारा से शासकीय प्राथमिक शाला कुसमी लंबाई 300 मीटर	18.99	14300.00

निविदा समय-सारणी एवं आवश्यक निर्देश:- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (1) ई-पंजीयन की छायाप्रति (2) निवास प्रमाण-पत्र (3) जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र चुक्ता प्रमाण (4) पेन कार्ड (5) अन्य जानकारी कार्यालीयन अवधि में देखा जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग
राजनांदगांव (छ.ग.)

जी-242504084/5

कांग्रेस की गाड़ी फिर रिवर्स गियर में

राशिद किदवई

विगत जून को 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा 240 सीटें जीतकर भी हार का एहसास कर रही थी, तो कांग्रेस 99 सीटें जीतकर भी विजय का एहसास कर रही थी। यह लाजिमी भी था। कुछ माह पहले तक अजेय नजर आने वाली भाजपा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जादुई अंक छूने से पहले ही रोक दिया गया था। वर्ष 2014 के बाद से यह पहला मौका था, जब राहुल गांधी अपने माथे पर से 'विफलता' के ठप्पे को हटा पाने में काफी हद तक कामयाब रहे थे। उन्होंने वायनाड और रायबरेली से न केवल बड़े अंतर से अपनी लोकसभा सीटें जीतीं, बल्कि पार्टी के वोटों की हिस्सेदारी को भी 19 फीसदी से बढ़ाकर 22 फीसदी करने में वह सफल रहे थे। विपक्षी दलों में कांग्रेस का परचम अचानक से बुलंद नजर आने लगा था। लेकिन पिछले छह महीनों में ही कांग्रेस की गाड़ी फिर से रिवर्स गियर में आ गयी लगती है। हरियाणा में प्रबल सत्ता-विरोधी लहर के बावजूद वहां कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी, तो अब महाराष्ट्र में सबसे बदतर हार ने कांग्रेस को फिर वहीं पहुंचा दिया है, जहां वह 2019 में खड़ी थी। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी के बावजूद हेमंत सोरेन ने जिस तरह से उप-मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस को देने से इनकार कर दिया है, उससे पार्टी की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा है। जम्मू-कश्मीर में भी कमोबेश यही स्थिति है, जहां राज्य की सत्ता में होने के बावजूद उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस की कोई खास पूछ-परख नहीं है। यह बात कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर इंडिया गठबंधन बना भी रहता है तब भी इसमें कांग्रेस की अहमियत कम हो जाएगी। एक 'बड़े भाई' वाला उसका जो दर्जा अब तक था, उससे वह वंचित हो सकती है। अगर इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना है, तो कांगेस को अब बाकी दलों के साथ समान हैसियत के साथ रहना होगा। वैसे भी इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पहले ही अलग हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रति उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसों की सहानुभूति भी अब शायद कम हो सकती है और वे भी अपनी-अपनी राह पर निकल सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए अब से लेकर 2029 तक का रास्ता काफी मुश्किलात भरा नजर आ रहा है। अगला विधानसभा चुनाव दिल्ली का है, वहां मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि कांग्रेस वहां भाजपा या आम आदमी पार्टी के गढ़ों में कोई कमाल दिखा सके। इसके बाद का पड़ाव बिहार है, जहां अक्तूबर-नवंबर, 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन पिछली बार जिस तरह के अनुभव राजद को हुए, उससे भी सियासत के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस को कोई अहमियत मिलेगी, इसकी संभावना नहीं है। अभी तो यही लगता है कि उसे लगातार अपमान के घूंट पीकर ही राजनीति करनी होगी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नतीजों को अप्रत्याशित बताते हुए इनकी विस्तार से समीक्षा करने की बात कही है। लेकिन इस पार्टी के साथ कड़वी हकीकत यह रही है कि इसमें जवाबदेही और पारदर्शिता हमेशा हाशिये पर रही है। नवंबर-दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में हार के कारणों की जांच के लिए गठित कमेटियों ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसी तरह मई, 2022 में आयोजित उदयपुर चिंतन शिविर के निष्कर्ष अब तक जयराम रमेश के लैपटॉप में ही बंद पड़े हैं। उन्हें कांग्रेस कार्यसमिति में चर्चा तक के लिए नहीं लाया गया है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह भी है कि जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुनील कोंगुलू जैसे 'जड़विहीन' नेताओं का संगठन पर इतना तगड़ा प्रभाव है कि तमाम पराजयों के लिए तीनों गांधी (सोनिया, राहुल, प्रियंका) और मल्लिकार्जुन खरगे का नेतृत्व ही कठघरे में नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा अब सांसद जरूर बन गयी हैं, लेकिन पार्टी में सुधार और एआइसीसी सचिवालय में पुनर्गठन की संभावना कम ही नजर आती है।

संभल हिंसा से सुलगते सवालों का जवाब आखिर कौन देगा?

कमलेश पांडे

कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती। भारत देश और भारतीय इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। मुहम्मद बिन कासिम जैसे मुस्लिम आक्रांताओं और उनके अनुगामियों ने तलवार की नोंक पर भारत की देशज सत्ता हथियाने के बाद यहां की सनातन सभ्यता-संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका हिसाब-किताब अब उनकी धर्मांतरित पीढ़ियों को देना पड़ रहा है। खासकर मंदिरों को ढहाकर जिन मस्जिदों का निर्माण किया गया, उनकी मुक्ति यानी जीर्णोद्धार का अभियान अब स्थानीय प्रशासन के गले की हड्डी बन चुकी है।

देखा जाए तो ऐसे मामलों में कभी आपसी विवाद, तो कभी न्यायिक आदेश के अनुपालन में सिविल व पुलिस प्रशासन को अपनी सक्रियता दिखानी पड़ती है, लेकिन कानून का राज स्थापित करने में उनकी विफलता से जब तब सांप्रदायिक दंगे भी भड़क जाते हैं जिससे धन-जन की भारी क्षति भी होती है। अतीत की बात यदि भुला दी जाए तो भी स्वतंत्र भारत की यह एक बड़ी चुनौती है, जबकि यह हिंदुओं के हिस्से का हिंदुस्तान है, क्योंकि मुस्लिमों को तो पाकिस्तान दे ही दिया गया, जिसका भाग ही बंगलादेश है।

लेकिन भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने के बजाय धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करना, फिर वोट बैंक की राजनीति के तहत मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाना और आतंकवाद पर समझौतापरस्त रुख अपनाने की प्रतिक्रियाओं में उभरे राष्ट्रवाद व हिंदुत्व की जनभावना ने जब बदले की कार्रवाई शुरू की तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों में खलबली मच गई। रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद और उसके न्यायसंगत समाधान ने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं के सत्ता की चूलें हिला दीं और हर ओर उनका पतन हुआ।

अब रामजन्मभूमि मुक्ति मिशन के पूरा होने के बाद न केवल मथुरा-काशी, बल्कि वैसे तमाम मंदिरों की मुक्ति के सवाल जनमानस में सुलगने लगे हैं, जिन्हें बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया था। चूंकि इतिहास खुद को दुहराता है, इसलिए अब धीरे-धीरे पुराने गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं, उखाड़े जाने लगे हैं। इसी कड़ी में उत्तरप्रदेश के संभल

जनपद के सदर तहसील स्थित दीपा सराय की जामा मस्जिद को जब हिंदू पक्ष श्री हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और उनके इसी दावे के आधार पर कोर्ट ने जब मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, तो फिर कानून के अनुपालन में कार्य कर रहे लोगों के विरुद्ध शांतिप्रिय समुदाय द्वारा बवाल काटने को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि संभल के कैला देवी मंदिर के ऋषिराज गिरी समेत आठ वादियों ने सिविल जज सीनियर डिविजन आदित्य कुमार सिंह की चंदौसी स्थित कोर्ट में इस बाबत एक वाद दाखिल किया है। जिसके दृष्टिगत कोर्ट ने कमिशन गठित कर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर 2024 को होगी। हिंदू पक्ष के एक स्थानीय वकील गोपाल शर्मा ने बताया है कि, कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि बाबरनामा और आइन- ए-अकबरी ने पुष्टि की है कि उस स्थान पर हरिहर मंदिर था। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर दिया था। लिहाजा इस मामले में उन्होंने कोर्ट में बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी का संदर्भ दिया है, जिनसे साफ होता है कि वहां हरिहर मंदिर था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगलकाल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।

लिहाजा, महंत ऋषि राज गिरि महाराज आदि ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे की मांग की थी। इस मामले में सिविल जज के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन मुख्य याचिकाकर्ता हैं। चूंकि चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की अदालत में वाद दाखिल किया था। इसलिए कोर्ट ने इसी याचिका पर 7 दिन में सर्वे रिपोर्ट मांगी है, जिसे 29 नवंबर को जमा करना है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव के नेतृत्व में टीम ने 19 नवंबर की शाम को ही सर्वे की शुरुआत कर दी थी। रविवार को टीम सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दोबारा मस्जिद पहुंची थी।

मसलन, कोर्ट से सर्वेक्षण का आदेश जारी होने के बाद मंगलवार को जब पहली बार सर्वे हुआ, तब से ही मुस्लिम समुदाय में असंतोष फैलने लगा और उस दिन भी विरोध हुआ था। क्योंकि मुस्लिम पक्ष मान रहा है कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई, उनको पर्याप्त समय या अवसर नहीं दिया गया। इसलिए सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में शांतिप्रिय समुदाय के लोग एकत्रित हो गए, जिससे स्थिति पहले तनावपूर्ण हुई, फिर अनियंत्रित हो गई। जिसे भारी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया गया।

बताया जाता है कि मस्जिद में आमतौर पर रविवार दोपहर में नमाज होती है। ऐसे में सर्वे करने वाली टीम को इससे पहले आने के लिए कहा गया था। सर्वे टीम के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सुबह साढ़े 7 बजे टीम पहुंची और 10 बजे तक सर्वे चला। फिर हम जरूरी तस्वीरें और विडियो लेकर जब निकलने लगे तभी भीड़ ने घेर लिया। फिर सर्वेक्षण टीम को सुरक्षित निकालने के क्रम में जो कुछ हुआ, वह न केवल योगी सरकार बल्कि शांतिप्रिय समुदाय के लिए भी एक कलंक है।

ऐसा इसलिए कि लखनऊ में बाजाप्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि, संभल में एक गंभीर घटना हुई। चुनाव के बारे में चर्चा को बाधित करने के लिए सुबह जानबूझकर एक सर्वेक्षण टीम भेजी गई थी। इसका उद्देश्य अराजकता पैदा करना था, ताकि चुनावी मुद्दों पर कोई बहस न हो सके। मैं कानूनी या प्रक्रियात्मक पहलुओं में नहीं जाना चाहता, लेकिन दूसरे पक्ष की बात भी नहीं सुनी गई। यह जानबूझकर भावनाओं को भड़काने और चुनाव में धांधली पर चर्चा से बचने के लिए किया गया था। संभल में जो कुछ हुआ, वह चुनावी गड़बड़ियों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी, सरकार और प्रशासन की ओर से किया गया था। हालांकि, सवाल यह भी है कि एक न्यायिक और प्रशासनिक कार्रवाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सियासी रंग क्यों दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग उनका वोट बैंक है? आखिर वह इस बात से अनजान क्यों हैं कि संभल जिला प्रशासन ने शनिवार को ही शांति भंग की आशंका में जिन 34 लोगों को 10 लाख रुपये तक के मुचलके पर पाबंद किया, उसमें सपा के संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क भी शामिल हैं। वहीं, इस मुचलके पाबंदी के ठीक एक दिन बाद वहां जिस तरह से आगजनी व फायरिंग की गई, जिसमें कुछ लोग हताहत भी हुए, उससे तो यही पता चलता है कि सर्वेक्षण टीम व पुलिस पर हमलावरों को सियासी संरक्षण प्राप्त है। तभी तो संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने एक अधिसूचना जारी कर किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को अधिकारियों के आदेश के बिना संभल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है।

बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिल वाद के आधार पर सर्वे के लिए रविवार सुबह सात बजे कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची तो संभल में बवाल हो गया। अचानक टीम के पहुंचने की सूचना पर जुटी भीड़ मस्जिद में दाखिल होने कोशिश करने लगी। फिर उन्हें रोकने पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हिंसक हुई भीड़ ने चंदौसी के सीओ की गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। इसी बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बवाल में घिरकर दो-तीन लोगों की मौत हो गई। कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए संभल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बता दें कि सर्वे टीम कोर्ट कमिश्नर चंदौसी के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सिंह राघव की अगुवाई में आई थी। संभल के डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई भी टीम के साथ थे। इसलिए बाहर हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठियां चलाकर सर्वे टीम को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। भले ही पुलिस के आक्रमक होते ही उपद्रवी भागने लगे, लेकिन कुछ देर बाद भीड़ फिर जुट गई और लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान छतों से फायरिंग होने लगी। मौके पर पहुंची अन्य जिलों की पुलिस और पीएसी के साथ अधिकारियों ने उपद्रव करती भीड़ से मोर्चा लिया।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतांक से आगे...

(7) यदि ब्राह्मणभाग को ऐतिहासिक अंश विशिष्ट होने के कारण वैदत्व से दूर रक्खा जाता है, तो ऐसा नित्य-इतिहास तो मन्त्र- आग में ठसाठस भरा पड़ा है, जिसका यास्कादि ने अपने ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख किया है तथा जैमिनि जी ने भी मीमांसादर्शन (पूर्वमीमांसा 1।1।31) के परन्तु श्रुतिसाम्यमात्रम् आदि सूत्रों में उसे व्यवस्थित किया है। ऐसी दशा में मन्त्र-ब्राह्मण के तुल्य होने से उनका वेदत्व भी तुल्य सिद्ध होता है, अतः वेद के अविशिष्ट अंश ब्राह्मण को पुराण नहीं कह सकते ।

(8) कहा जाता है कि ब्राह्मणग्रन्थ मन्त्रों का व्याख्यान हैं, अतः वे वेद नहीं, बल्कि पुराण होने चाहियें। यदि यह तर्क ठीक है तब तो सब मन्त्र भी अकेले कार का व्याख्यान हैं, अतः वे भी वेद नहीं होने चाहियें।

मन्त्रों का व्याख्यानत्व और ओंकार का व्याख्येयत्व परम्परा- ध्याय में भली भांति सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए जिस प्रकार प्रणव का व्याख्यानभूत समस्त मन्त्रभाग वेद है इसी प्रकार मन्त्रभाग का व्याख्यान भूत ब्राह्मणभाग भी वेद ही हो सकता है पुराण नहीं?

इस प्रकार हम युक्तियों और प्रमाणों द्वारा ब्राह्मणभाग का वेदत्व सिद्ध करने के बाद एक बार पाठकों का ध्यान पूर्वप्रतिपादित प्रमाणाध्याय की ओर आकृष्ट करते हुवे यह कह देना चाहते हैं कि वेदोपदेश काल से ही जो वर्तमान पुराणों का मूलभूत एक अरब प्रमाण वाला आदिम-पुराण चला आता था उसी को लक्ष्य करकै समस्त वैदिक साहित्य में पुराण शब्द का निर्देश किया गया है।

न कभी ब्राह्मण ग्रन्थों की पुराण संज्ञा थी और न कोई साक्षर भविष्य में उन्हें पुराण कहने का साहस कर सकता है!

क्रमशः ...

खुली किताब की तरह था हरिवंशराय बच्चन का जीवन

कृष्ण प्रताप सिंह

हरिवंशराय बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वह 'मधुशाला' के बाद कुछ नहीं रचते, तो भी भुलाये नहीं जाते और हिंदी साहित्य के आकाश के सबसे चमकीले तारे के रूप में उनकी जगह सुरक्षित रहती। 'मधुशाला' ने उनके समय में ही लोकप्रियता के कई पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर डाले थे। जैसे ही उन्हें काव्यपाठ के लिए बुलाया जाता, लोग उनसे बारंबार 'मधुशाला' के ही छंद सुनाने का आग्रह करने लगते। उसकी इस लोकप्रियता ने उन्हें संकट में भी डाल दिया था।

दरअसल, कुछ ईर्ष्यालु कवियों ने महात्मा गांधी से यह कहते हुए उनकी शिकायत कर डाली थी कि वह 'मधुशाला' की मार्फत मद्यपान का प्रचार करने पर आमादा हैं। ये कवि महानुभाव महात्मा से

यह मांग करने से भी नहीं चूके थे कि चूंकि वह मद्यनिषेध के पैरोकार हैं, इसलिए 'मद्यपान के इस प्रचारक' को कांग्रेस के कवि सम्मेलनों में न बुलवाया करें।

फिर तो बच्चन जी कवि सम्मेलनों में यह कहकर 'मधुशाला' के छंद सुनाने लगे थे कि यह अपने पाठकों व श्रोताओं को मस्ती में ही नहीं झुमाती, गुलामी की व्यापक निराशा से विकल व मूक हो गये देश के मध्य वर्ग के विक्षुब्ध व वेदनाग्रस्त मन को वाणी देती है। साथ ही, प्यार की तड़प व लालसा का इजहार और जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतिकार करना भी सिखाती है। अपनी बात को 'प्रमाणित' करने के लिए वह मधुशाला के इस छंद का खास तौर पर उल्लेख किया करते थे ='छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला/आने के ही साथ जगत में कहलाया 'जानेवाला/स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी/बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन-मधुशाला।'

वह 'मधुशाला' पर ही नहीं रुके रहे और निरंतर सृजनरत रहकर पद्य के साथ गद्य को भी समृद्ध करते रहे। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने चार खंडों में आत्मकथा लिखी, जिसने सुहृदजनों की भरपूर प्रशंसा अर्जित की। आत्मकथा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित 'सरस्वती सम्मान' तो मिला ही, 'धर्मयुग' के संपादक धर्मवीर भारती ने यह तक कह डाला कि इससे पहले हिंदी में ऐसी आत्मकथा लिखी ही नहीं गयी, जिसमें लेखक ने अपने बारे में बताते हुए न कोई छद्म रचा, न कुछ छिपाने की जरूरत महसूस की हो। बच्चन ने आत्मकथा के पहले खंड 'क्या भूलूं क्या याद करूं' में चारों खंडों की 'प्रस्तावना' के तौर पर यह भावप्रवण गीत दिया था = 'क्या भुलूं, क्या याद करूं मैं!/अगणित उन्मादों के क्षण हैं/अगणित अवसादों के क्षण हैं/रजनी की सूनी घड़ियों को किन-किन से आबाद करूं मैं!/क्या भुलूं, क्या याद करूं मैं!/याद सुखों की आंसू लाती/दुख की, दिल भारी कर जाती/दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं!' वर्ष 1926 में जब वह सिर्फ 19 वर्ष के थे, 14 वर्षीया श्यामा देवी से विवाह के बंधन में बांध दिये गये थे। लेकिन दांपत्य के 10 ही साल बीते थे कि क्षय रोग ने श्यामा को असमय ही काल का ग्रास बना लिया। इससे बच्चन का जीवन बैठ कर रह गया।

सियासी भंवर में बांग्लादेश, समय से पहले चुनाव की मांग

महेंद्र वेद

अपनी सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन के बीच जब बीते अगस्त में शेख हसीना बांग्लादेश से भाग गईं, तो उनकी धुर राजनीतिक विरोधी और दो बार की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया की प्रतिक्रिया थी, 'हमें लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाना होगा।' इससे बांग्लादेश पर नजर रखने वाले लोग हैरान रह गए, जिन्हें यह उम्मीद थी कि जिया शेख हसीना के मुल्क भागने पर खुश होंगी, जिन्होंने उन्हें 2018 से जेल में रखा और कथित रूप से उचित चिकित्सा देखभाल से वंचित रखा था। शायद, पीड़ा ने जिया को इतना समझदार बना दिया है कि अब वह फिर से राजनीतिक गतिविधि शुरू कर सकती हैं, और एक निष्पक्ष चुनाव में जीत की भी उम्मीद कर सकती हैं।

चार दशकों से अधिक समय तक सक्रिय रहने के कारण, वह जानती होंगी कि राजनीति और चुनाव उनके देश में व्यावहारिक रूप से हर चीज को संचालित करते हैं। उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने मांग की कि भारत में निर्वासन में रह रहीं हसीना को वापस लाया जाए और उनके शासन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों की मौत और भ्रष्टाचार के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन न तो जिया और न ही बीएनपी इस मांग का समर्थन करते हैं कि हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसे चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाए। राजनीतिक तर्क बताता है कि बेगम जिया चाहेंगी कि अवामी लीग के फिर से पांव जमाने से पहले चुनाव हो जाएं। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम ने कहा कि अवामी लीग राजनीतिक दल है और अगर वे चुनाव लड़ते हैं, तो जनता फैसला करेगी।

वास्तव में इस मुद्दे पर बीएनपी का रुख जमात-ए इस्लामी और अन्य इस्लामी समूहों से अलग है। इस्लामी समूह चाहते हैं कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन छात्र नेताओं के विचारों से अलग है, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और वर्तमान में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में प्रमुख पदों पर हैं। सरकार ने चुनाव सुधारों का अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए एक समिति नियुक्त की है, जो दीर्घकालिक प्रक्रिया है। यह मोहम्मद यूनुस के लिए दुविधा की स्थिति है, जो सुधारों के लिए उत्सुक हैं, लेकिन इसे प्रमुख खिलाड़ियों के बीच 'आम सहमति' के लिए छोड़ने पर तैयार हैं। उन्होंने द डेली स्टार अखबार से कहा, 'हम कुछ भी थोप नहीं रहे हैं। हम सिर्फ व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और अगर राजनीतिक दल तय करते हैं कि सुधार जरूरी नहीं हैं, तो चुनाव और भी जल्दी हो सकते हैं। हम शासकों की तरह काम नहीं कर रहे हैं। हम यहां सिर्फ सुविधाकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं।'

साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सुधारों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करते हुए सरकार पार्टी के 'आकार' के अनुसार पक्ष और विपक्ष का फैसला करेगी। छात्र और इस्लामी समूह, खासकर जमात, इसे किस तरह से लेते हैं, यह देखना होगा। जमात के लोगों ने 1971 में बांग्लादेश के उदय का विरोध किया था। मुल्क की आजादी के बाद जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे सैन्य शासन के दौरान हटा लिया गया, लेकिन बाद में फिर हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। एक और पहलू यह है कि जमात बीएनपी की सहयोगी थी और वर्ष 2001-2006 के दौरान जिया की सरकार में उसके दो नेता महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर थे। रिकॉर्ड पर आधारित एक सीधा आकलन यह दर्शाता है कि अवामी लीग को हराने के लिए बीएनपी को जमात एवं अन्य इस्लामी समूहों के साथ हाथ मिलाना होगा। क्या जिया उनके साथ हाथ मिलाने के लिए राजी होंगी?

इससे उन्हें अवामी लीग के मुकाबले कम लाभ होगा, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। हसीना के पलायन के बाद अवामी लीग को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके कई कार्यकर्ताओं को मार दिया गया या उन्हें घरों और दफ्तरों से भगा दिया गया। लीग ने पहले भी ऐसी स्थितियों का सामना किया है। हसीना की गैर-मौजूदगी और किसी परिजन के सक्षम नेतृत्व के अभाव के बावजूद अवामी लीग खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि हाल में बैठकें आयोजित करने के इसके प्रयासों को अनुमति नहीं दी गई। जहां तक हसीना का सवाल है, यूनुस सरकार ने दबाव बनाए रखने की कोशिश की है। यूनुस और उनके अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि वे उनके प्रत्यर्पण की मांग करेंगे।

भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, लेकिन उसमें एक प्रावधान है, जो किसी पक्ष को 'राजनीतिक कारणों से' प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं देता है। हसीना के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप में कई मामले दर्ज किए गए हैं। उन पर 'युद्ध अपराधों' के लिए मुकदमा चलाने की भी मांग की गई है, ठीक उसी तरह, जैसे उनकी सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण ने 1971 के आंदोलन के दौरान पाकिस्तानी सेना का सहयोग करने के आरोप में जमात के कई लोगों और एक वरिष्ठ बीएनपी नेता पर मुकदमा चलाकर दोषी ठहराया था और फांसी पर लटका दिया था। ढाका ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) और इंटरपोल से भी संपर्क किया है। यह मानते हुए कि भारत उन्हें वापस भेजने पर सहमत हो जाएगा या उनका प्रत्यर्पण आईसीटी या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप से हो जाएगा, हसीना की बांग्लादेश वापसी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दे सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह अवामी लीग को उत्साहित कर सकता है। क्या ऐसी स्थिति में भी बीएनपी चुनाव करवाना चाहेगी, यह स्पष्ट नहीं है।

बांग्लादेश की नाजुक राजनीतिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने खुलासा किया कि हसीना का कोई त्यागपत्र उनके पास नहीं है। इससे सभी संबंधित लोग परेशान हो गए और राष्ट्रपति को हटाने तक की मांग करने लगे। लेकिन उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए संसद ही मौजूद नहीं है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनका सम्मान किया था और उन्होंने अपने अमेरिकी दौरे में रिपब्लिकन पार्टी के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप यूनुस के शासन के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों पर 'बर्बर हमलों' की कड़ी निंदा करते हुए ट्वीट करने के लिए मजबूर हुए। यूनुस ने इसे 'निराधार' और 'प्रचार' बताते हुए कहा कि यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान कही गई थी। लेकिन ऐसी घटनाओं के जारी रहने की खबरों के कारण उनकी स्थिति कमजोर है। समय से पहले चुनाव की मांग उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है।

आज का इतिहास

1990 ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन की महारानी को अपना इस्तीफा सौंपा था।

1995 27 उपस्थित राष्ट्रों द्वारा बार्सिलोना संधि पर हस्ताक्षर किया गया।

1996 कैप्टन इन्द्राणी सिंह एयरबस ए-300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनी।

1997 तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल ने इस्तीफा दिया।

2002 आत्मघाती हमलावरों ने केन्या के मोम्बासा में एक इजरायल के स्वामित्व वाले होटल को उड़ा दिया, लेकिन उनके सहयोगियों ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ अरकिया इज़राइल एयरलाइंस चार्टर उड़ान को लाने के अपने प्रयास में विफल रहे।

2006 फ्रांसीसी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि फ्रांसीसी बलों द्वारा समर्थित मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सरकारी सैनिकों ने विद्रोहियों के उत्तरपूर्वी शहर को फिर से गिराने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू किया है।

2007 गुगल ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जियो थर्मल पावर सहित नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान पर लाखों डॉलर का निवेश करने की योजना की घोषणा की।

2008 पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी ने अपने नेताओं के तीसरे सेट को तैयार किया है, अगर इसके पहले और दूसरे सेट को गिरफ्तार या हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी तक नेताओं के नामों की घोषणा नहीं की गई है।

2009 पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा अक्टूबर 2007 में जारी किया गया था ताकि कई हजार राजनेताओं (वर्तमान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सहित) को राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिल सके।

2010 संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना और दक्षिण कोरियाई नौसेना उत्तर कोरिया की चेतावनियों के बावजूद कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिम में पानी में अभ्यास करती है।

2011 सूडान की सरकार केन्या के राजदूत को निष्कासित करती है, केन्याई उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कि वह केन्या में प्रवेश करने पर सूडान के राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को गिरफ्तार करेगी।

2012 यूरोपीय आयोग ने तीन प्रमुख स्पैनिश बैंकों (बंकिया, एनसीजी बैंको और कैटलुन्या बैंच) को सिकोड़ने और पुनर्गठन की एक स्पेनिश सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है।

2012 सीरिया की राजधानी दमिश्क में दो कार बम धमाकों में 54 मरे और 120 घायल हुये।

ठाकरे की चमक को वापस लाने के लिए फिर से साथ आएंगे उद्धव-राज?

अभिनय आकाश

महाराष्ट्र के चुनावी कैंपेन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए नारे की गूंज चारो ओर नजर आई और काफी चर्चा में भी रही। इसके अलावा कैंपेन के आखिरी दिन पीएम मोदी ने एक नया नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे दिया। बीजेपी का कहना था कि अलग अलग धर्मों, जातियों और समुदायों में नहीं बंटना है बल्कि हमें नए भारत के लिए वोट करना है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ठाकरे परिवार की राजनीति को ऐसा झटका लगा कि जो ठाकरे परिवार कभी सत्ता के समीकरण का केंद्र हुआ करता था। अब हार की हताशा से जूझ रहा है। नतीजों से साफ हो गया है कि न सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे का राजनीतिक रसूख खत्म हो गया है बल्कि उद्धव ठाकरे भी अपने पिता के बनाए राजनीतिक साम्राज्य को कायम नहीं रख पाए हैं। उद्धव की शिवसेना और राज की मनसे दोनों ही इस चुनाव में अपनी जमीन बचा पाने में नाकाम रहे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जिनके पीछे कभी लाखों समर्थक खड़े होते थे आज उनकी पार्टियां सियासी फर्श पर लड़खड़ा रही हैं। हार की ये कहानी केवल चुनाव की नहीं बल्कि उस दिन शुरू हुई थी जब ये दोनों भाई एक दूसरे के विरोधी बन गए। एक वक्त था जब ठाकरे नाम राजनीति का ब्रांड हुआ करता था। मजबूत, शक्तिशाली और अजेय हुआ करता था। लेकिन आज ये नाम राजनीति के मैदान में दिशाहीन घूम रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? सवाल ये भी उठता है कि परिवार के बंटने से जो वोट कट गए हैं क्या वो एक होकर फिर से सेफ हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को सहेजने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक हो सकते हैं। या फिर असली शिवसेना का जो ठप्पा एकनाथ शिंदे ने अपने कंधे पर लगा लिया है वो हमेशा हमेशा के लिए अमिट हो गया है।

याद करिए, बाला साहब ठाकरे का वो दौर। एक ऐसा नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में शेर की दहाड़ जैसा गूंजता था। हाथ में रूद्राक्ष की माला शेर की दहाड़ वाली तस्वीर और आवाज तानाशाह वाली। सब कुछ राजनीति नहीं थी। राजनीति को खारिज कर सरकारों को खारिज कर खुद को सरकार बनाने या मानने की ठसक थी। उन्होंने सांसद भी बनाए और मेयर बनाए तो मुख्यमंत्री भी। मी मुंबईकर का नारा लगाकर मराठियों को जोड़ा और मी हिंदू की राजनीति कर हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाने लगे। अंग्रेजी का मशहूर फ्रेज है 'either you can agree or disagree but you cannot ignore him.' यानी आप आप सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं वहीं हमारे लिए सिंहासन होता है... ये कथन बाला साहेब ठाकरे के थे। उनके भाषण की गूंज दादर से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ती थी। उद्धव और राज उनके दो सिपहसालार शिवसेना की ताकत के दो स्तंभ थे। राज की आक्रमक शैली, उद्धव की रणनीतिक सोच और बाल ठाकरे का करिश्मा ये तिकड़ी राजनीति के अखाड़े में ट्राइ टेस्टेड थी। लेकिन 2005 में ये राजनीतिक परिवार सत्ता की महत्वकांक्षा का शिकार हो गया। ठाकरे परिवार की सियासी रामायण में लक्ष्मण रेखा खिंच गई। राज को लगने लगा कि पार्टी की गद्दी पर उनका हक है। लेकिन उद्धव के शांत स्वभाव ने पार्टी के बड़े नेताओं का भरोसा जीत लिया। कहते हैं राज की दहाड़ कमला की थी। लेकिन उद्धव की मुस्कान ज्यादा असरदार साबित हुई। पहले उद्धव ठाकरे के मुकाबले वाली समानांतर राजनीति में राज ठाकरे की एक खास अहमियत बनती थी क्योंकि राज ठाकरे को शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे वाले राजनीतिक मिजाज का नेता माना जाता था। और ये कोई हवा हवाई बातें नहीं थीं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक खास कद भी अख्तियार किया था। राज ठाकरे को असली टैलैंट और उद्धव

ठाकरे को पिता की विरासत के कारण राजनीति में आये नेता ही माना जाता था।

2005 में राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। राज ठाकरे उसी चाल पर चलना चाहते थे जिस धार पर चलकर बाल ठाकरे ने अपनी उम्र गुजार दी। 27 नवम्बर 2005 को राज ठाकरे ने अपने घर के बाहर अपने समर्थकों के सामने घोषणा की। मैं आज से शिवसेना के सभी पदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। पार्टी क्लर्क चला रहे हैं, मैं नहीं रह सकता। हालांकि राज ठाकरे का पार्टी छोड़कर जाने का दुख बाल ठाकरे को हमेशा से रहा। लेकिन 16 साल की राजनीति में राज ठाकरे के हाथ अब तक कुछ खास नहीं लग सका है। पुरानी कहावत है खोखा चना बाजे घना यानी अंदर जब कंटेंट नहीं होगा तो आप कितना भी बढ़ते रहिए प्रभावशाली नहीं होगा। इस वजह से उनकी पार्टी लगातार सिकुड़ती चली गई। एक वक्त ऐसा भी था कि उनके 13 विधायक जीतकर आए थे। दो बार से विधायकों के लाले पड़े हैं। लगातार ऐसा दूसरा चुनाव है जहां उन्हें जीरो सीटें मिली हैं। राज ठाकरे की कन्फ्यूज वाली राजनीति लोगों को भी भ्रमित कर रही है। अचानक उत्तर भारतीयों को भगाने लगते हैं। फिर महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते हैं। कभी हिंदू हृदय सम्राट बन जाते हैं। अयोध्या काशी और मथुरा की बात करने लगते हैं। फिर उन्हें उत्तर भारतीय भी हिंदू और अपने लगने लगते हैं। कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगते हैं। कभी नरेंद्र मोदी की बुराई करने लगते हैं। मतलब लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हो किसकी तरफ। कभी शरद पवार की तारीफ कर देंगे तो कभी कांग्रेस के साथ बात करने चले जाएंगे। कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात करते हुए मोदी-शाह की तारीफ, कभी गुजरात बनाम महाराष्ट्र करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति की वजह से उनकी हालत हुई है।

बाल ठाकरे का आशीर्वाद उद्धव के साथ था। लेकिन राज के पास भाषणों का तड़का था। दोनों को लगा हम अकेले ही काफी हैं। लेकिन तब इन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। कहानी तब और मजेदार हो गई जब 2019 में उद्धव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से किनारा कर लिया और महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार बना ली। उधर राज ने बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का अनकहा समर्थन किया। दोनों भाई अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे। 2024 के चुनाव में उद्धव की शिवसेना यूबीटी और राज की मनसे दोनों ही जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए। उद्धव जो बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे। आज न पार्टी का नाम बचा पाए और न चुनाव निशान। वहीं राज जिनके भाषणों की गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देती थी। अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सिमट कर रह गए। राज ने सोचा था कि मराठी मानुष का मुद्दा उन्हें सत्ता दिलाएगा। लेकिन जनता ने सोचा कि ये तो पुराना हो गया, कुछ नया लाओ। उद्धव ने सोचा कि गठबंधन की राजनीति से कुर्सी पक्की हो जाएगी। लेकिन उनकी पार्टी ही टूट गई। नतीजा कि ठाकरे नाम की राजनीति का ग्राफ इतना गिर गया कि अब ये नाम इतिहास की किताबों का किस्सा बनने की कगार पर है। ये वो सबक है जो इन भाईयों ने नहीं सीखा। उद्धव और राज की लड़ाई ने शिवसेना को कमजोर तो किया ही ठाकरे नाम की चमक को भी फीका कर दिया। 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले उद्धव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनती पार्टी का साथ क्या छोड़ा पूरी पार्टी ने ही उद्धव को किनारे लगा दिया। जैसे ही एकनाथ शिंदे को मौका मिला उन्होंने पार्टी तोड़ दी और बीजेपी के साथ हो लिए। वो न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति को ही खत्म कर दिया। महाराष्ट्र के सियासी बैटल के सबसे बड़े खिलाड़ी तो वो नेता बनकर उभरे जिन्हें चुनाव के दौरान मंचों से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ने गद्दार कहकर हर बार संबोधित किया। 2024 में तो एकनाथ शिंदे ने ये साबित भी कर दिया है कि असली शिवसेना और उसका वारिस ठाकरे परिवार नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने गद्दार को ही असली हकदार मान लिया। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का एजेंडा विरासत में मिला था, लेकिन अभी तो लगता है जैसे सब कुछ गवां दिया हो। अब पांच साल तक तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को इसी नतीजे से संतोष करना होगा। अगर उन्हें बाल ठाकरे की विरासत बचानी है व फिर से शिवसेना का वर्चस्व महाराष्ट्र में कायम करना है। फिर से खुद को साबित करना है। तो शायद उनकी एकजुटता ही इसमें मदद कर सकती है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी भी तो कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं। परिवार एक रहा तो विरासत भी एक रहेगी। वरना उद्धव और राज के मनसे के अलग अलग लड़ने से इनके वोट कैसे कटे हैं महाराष्ट्र 2024 का नतीजा इसका गवाह है।

चीन से भरोसेमंद रिश्तों की बंध रही उम्मीद?

शोभना जैन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पांच वर्ष की चुप्पी के बाद रिश्तों को पटरी पर लाने की जो कवायद कुछ समय पूर्व शुरू हुई, उसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए इस सप्ताह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस। जयशंकर के साथ चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच सकारात्मक बातचीत हुई और इसके अनुरूप कदम उठाए जाने को लेकर सहमति बनी। इससे रिश्तों को सामान्य बनाने की एक उम्मीद तो बंधी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन इस बार इस भरोसे को बनाए रखेगा? यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश पुरानी कड़वाहट को भुलाकर रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बार फिर बातचीत के लिए आमने-सामने बैठे। लेकिन भारत का साफतौर पर कहना है कि सीमा पर जब तक शांति कायम नहीं होगी, चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 में भारतीय सैन्य टुकड़ी पर चीन के सैनिकों द्वारा किए गए अचानक नृशंस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तल्ख रिश्ते और भी तल्ख हो गए थे।अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लगभग पांच वर्ष बाद बातचीत से दो दिन पूर्व ही दोनों देशों की सेनाओं ने सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में हुई। सहमति के बाद उस क्षेत्र में डेमचोक और देपसांग में पिछले माह ही अपनी-अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर दिया, जिससे दोनों देशों के शिखर नेताओं के बीच ब्रिक्स के दौरान कजान में बातचीत का एक सकारात्मक माहौल बनाया जा सका। वार्ता में दोनों शिखर नेताओं ने आपसी सहमति के अनुरूप एक-दूसरे देश की सेना को विवादास्पद क्षेत्र से पीछे हटाने, गश्त दोबारा शुरू करने सहित संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अनेक स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के निर्देश दिए। दोनों देशों के बीच हाल ही में जिस तरह से सीमा विवाद के मुद्दे पर पांच वर्ष बाद विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता जल्द बुलाने, सीधी उड़ान बहाल करने और मानसरोवर तीर्थयात्रा दोबारा शुरू करने आदि के बारे में सहमति हुई है, उससे सीमा पर शांति बहाल होने की उम्मीद की जानी चाहिए। वैसे भी सीमा विवाद के बावजूद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध लगातर अच्छे रहे। सीमा विवाद के साथ ही दोनों देशों के बीच अनेक अहम विचाराधीन मुद्दे हैं, जिस दिशा में इस तनाव के चलते काम रुका पड़ा है। मसलन नदियों के आंकड़े साझा करने जैसे मुद्दे, जिसका असर भारत को सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप के रूप में देखने को मिलता है। वर्ष 2017 में बाढ़ के आंकड़े इकट्ठा करने वाले केंद्रों को हुए नुकसान का कारण बताकर चीन ने जल विज्ञान संबंधी डाटा साझा करने की प्रक्रिया रोक दी थी। हालांकि बीच-बीच में कुछ समय के लिए डाटा देना चालू किया गया था लेकिन सीमा पर तनाव होने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। बहरहाल, जिस तरह से दोनों देशों ने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाने शुरू किए हैं, उससे एक उम्मीद तो बनी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि चीन भरोसा जगाए, कथनी-करनी में फर्क दूर करे और इस भरोसे को बनाए रखने के लिए अपना विस्तारवादी एजेंडा परे रख कर सीमा पर शांति बनाए रखे।

समग्र एवं समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही 'सुक्खू सरकार'

कर्नल डा. धनी राम शांडिल

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के समग्र और समावेशी विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। नवोन्मेषी पहल के साथ अनेक योजनाएं और कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इसके सामानांतर, प्रदेश भाजपा के नेता सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए राज्य की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेता सत्ता से बेदखल होने के 2 साल बाद भी क्षुब्ध हैं। वह यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि प्रदेश की जनता ने उन्हें वर्ष 2022 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

भाजपा नेता झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां अर्जित की हैं वे पूर्व भाजपा सरकार की 5 साल की उपलब्धियों से कहीं ज्यादा हैं। प्रदेश सरकार ने समाज व विभिन्न क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में अनेक जनहितैषी निर्णय लेकर जनता को लाभान्वित किया है। राज्य सरकार प्रदेश के वंचित वर्ग के कल्याण को

सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है ताकि समाज में पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार 5 गारंटियों को पूर्ण कर राज्य के लाखों लोगों को लाभान्वित किया है और अन्य गारंटियां भी चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं।

हिमाचल प्रदेश के 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए ओ.पी.एस. बहाली, महिलाओं को 1500 रुपए प्रदान करने के लिए 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना', 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना, पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करना और गाय व भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना सहित अनेक पहल शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' घोषित कर उनका पालन-पोषण राज्य सरकार कर रही है और भाजपा के नेता इन सब कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं।

डा. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पात्र मेधावी छात्रों को देश एवं विदेशों में पढ़ाई के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य व शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है जिन्हें पूर्व भाजपा सरकार ने पूरी तरह से पंगु बनाने की कोशिशें कीं। इन संस्थानों को जर्जर स्थिति से उभारने के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान और सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य संसदीय सचिव कानून को लेकर भाजपा नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उसी कानून के तहत पूर्व में प्रदेश में रही भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां होती रही हैं। अभी यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है तथा इस मामले में राज्य सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है।

प्रदेश सरकार में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर होने वाली नियुक्तियों को लेकर भी भाजपा को स्मरण रहना चाहिए कि उनकी सरकारों के दौरान भी इस प्रकार की नियुक्तियां की गई हैं। पूर्व भाजपा सरकार के समय में 50 से ज्यादा अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की फौज तैनात की गई जबकि कांग्रेस सरकार में लगभग 20 पदों पर ऐसी नियुक्तियां हुई हैं। जनमंच के नाम पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, जबकि वर्तमान सरकार ने राजस्व लोक अदालतें लगाकर अढ़ाई लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया है। प्रदेश सरकार ने 2 साल में 30 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। न्यायालय में विचाराधीन मामलों के दृष्टिगत लंबित भर्तियों की दक्षतापूर्वक पैरवी कर युवाओं का नौकरी पाने का सपना साकार किया है।

प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार का रवैया भी पक्षपातपूर्ण रहा है। प्रदेश के भाजपा नेता अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर अड़ंगे लगा रहे हैं। केंद्र ने प्राकृतिक आपदा के दौरान भी प्रदेश की कोई मदद नहीं की और प्रदेश भाजपा के नेता आपदा में भी स्वार्थ की राजनीति करते रहे। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावितों की हरसंभव मदद के लिए 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज प्रदान किया। प्रदेश सरकार राज्य को आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

महाराष्ट्र के नतीजों से बदलेंगे विपक्षी राजनीति के समीकरण

कृष्णमोहन झा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीत कर लोकसभा की सदस्य बन चुकी हैं। उन्होंने 4 लाख से भी अधिक मतों से जीत हासिल कर पहली बार संसद सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया है और चुनाव परिणाम की घोषणा के एक सप्ताह के अंदर ही सदन में अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा दी है। संभवत: यह पहला अवसर है जब गांधी परिवार के तीन सदस्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में एवं श्रीमती सोनिया गांधी राज्य सभा में एक साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं परंतु वायनाड उपचुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बावजूद कांग्रेस सदस्यों के चेहरों पर विजेता जैसी चमक नहीं है जिसका एक मात्र कारण यह है कि हाल में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में उसे अत्यंत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर संसद के शीतकालीन सत्र में भाग ले रहे भाजपा सांसदों के चेहरों पर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक विजय से उपजा उल्लास और उमंग स्पष्ट देखा जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाने की उम्मीद लगाए बैठे इंडिया गठबंधन के घटक दलों में कांग्रेस की हताशा बाकी दलों से कहीं अधिक है वैसे कमोवेश यही हाल शिव सेना (उद्धव ठाकरे) और एनसीपी (शरद पवार) का भी है । इंडिया गठबंधन के ये तीनों घटक दल यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के जिन मतदाताओं ने 18 वीं लोकसभा के चुनावों में उन्हें सर आंखों पर बिठाया था उन्हीं मतदाताओं ने आखिर राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत का हकदार क्यों मान लिया। अब उन दलों को इस हकीकत को स्वीकार करना ही होगा कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई लोकप्रियता को चुनौती देने का सामर्थ्य और साहस नहीं है।

महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणामों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि देश की राजनीति एक बार फिर न ई करवट ले रही है। 18 वीं लोकसभा के चुनावों में 99 सीटों पर मिली जीत के बाद कांग्रेस पार्टी जिस उमंग और उल्लास से

लबरेज दिखाई दे रही थी उसकी चमक को महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने फीका कर दिया है। दरअसल इसकी शुरुआत तो कुछ माह पूर्व संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा के चुनावों से हो गई थी जहां वह एक दशक बाद सत्ता पर काबिज होने का सुनहरा स्वप्न संजोए बैठी थी लेकिन हरियाणा में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच अंदरूनी खींचतान और अति आत्मविश्वास के कारण सदन के अंदर उसे लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजेदार बात तो यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी में भावी मुख्यमंत्री बनने के लिए एकाधिक दावेदार सामने आ चुके थे लेकिन एक दशक बाद भी कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई।

हरियाणा जैसा अतिआत्मविश्वास ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ,एनसीपी (शरद पवार) और शिव सेना (उद्धव ठाकरे) की उम्मीदें टूटने का कारण बन गया। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने तीनों पार्टियों के पैरों तले की जमीन ही खिसका दी है । हरियाणा में कांग्रेस कम से कम इतनी सीटें जीतने में तो कामयाब हो ही गई थी कि वह विधानसभा के अंदर सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा सके परन्तु महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम तो यह संकेत दे रहे हैं कि वहां उक्त तीनों पार्टियों को हताशा की स्थिति से उबरने में लंबा वक्त लग सकता है । उद्धव ठाकरे की नेतृत्व क्षमता पर सवाल लग चुका है। एनसीपी से बगावत कर के अजित पवार ने शरद पवार के नेतृत्व को जो चुनौती दी थी उससे निपटने में वे सफल नहीं हो पाए।

कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में कोई इतना लोकप्रिय चेहरा नहीं है जिससे पार्टी किसी करिश्मे की उम्मीद कर सके। कुल मिलाकर आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। झारखंड में कांग्रेस को जो सफलता मिली है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाने से मिली है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का साथ लोकसभा चुनावों में उसके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ परंतु हाल में संपन्न राज्य की नौ विधानसभा सीटों के उपचुनाव में किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा न करने का उसका फैसला यही संदेश देता है कि समाजवादी पार्टी के साथ उसके संबंधों में अब पहले जैसी मधुरता नहीं रह गई है। दिल्ली में तो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ उसके रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे । दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनावों पर इस बयानबाजी का असर पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा के अगले चुनावों में भाजपा से कड़ी चुनौती मिलना तय है। देश का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य यह संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं जिनमें एनडीए गठबंधन में भाजपा तो अपना वर्चस्व बनाए रखने में कामयाब रहेगी लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को अपना वर्चस्व बनाए रखने में दिक्कत आ सकती है। यह भी उत्सुकता का विषय है कि संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रवेश राहुल गांधी की ताकत और मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा अथवा प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के तुलना होने लगेगी। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी वाड्रा यह कभी नहीं चाहेंगी कि संसद में राहुल गांधी के साथ उनकी तुलना की जाए।

अदाणी की आड़ में अमरीका द्वारा भारत की बांह मरोड़ने की चाल

योगेन्द्र योगी

अमरीका की यह खासियत है कि यदि उसके हितों पर जरा भी आंच आ जाए तो वह दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ कैसी भी कूटनीति रच सकता है। मानवाधिकार और पर्यावरण सहित तमाम ऐसे मुद्दों पर अमरीका की दोहरी नीति इसका प्रमाण रही है। उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करके अमरीका ने एक बार फिर भारत की बांह मरोडने का प्रयास किया है। अमरीका की तकलीफ यह है कि भारत आंख बंद करके उसका अनुयायी नहीं बन रहा है। भारत विश्व में अपनी अलग ताकत बनाने में क्यों जुटा हुआ है। भारत ग्लोबल साऊथ के लीडर के तौर पर कैसे उभर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे दिनों-दिन मजबूत होती जा रही है। भारत के उन देशों से रिश्ते क्यों हैं, जिन्हें अमरीका नापसंद करता है। ये चंद सवाल हैं जोकि अमरीका को परेशान किए हुए हैं। इसी वजह से अमरीका गाहे-बगाहे भारत को दोस्ती की आड़ में दबाने की कोशिश करने से बाज नहीं आता।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूरोप की यात्रा के दौरान साफ शब्दों में अमरीका और यूरोपीय देशों को बता दिया था कि जो मुद्दे इनके हैं, वे जरूरी नहीं कि भारत के भी हों। भारत का दुनिया को देखने का अपना नजरिया है। अमरीका को भारत के रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध भी नागवार गुजरते हैं। भारत कच्चा तेल रूस से खरीद कर यूरोप और अमरीका को आपूर्ति करता है। रूस की तरह ईरान पर भी अमरीका ने मनमाने प्रतिबंध लगा रखे हैं। जबकि भारत और ईरान के दोस्ताना ताल्लुक हैं। यह भी अमरीका को पसंद नहीं है। अमरीका किसी न किसी बहाने भारत को दबाव में लाने की फिराक में रहता है। गौतम अदाणी पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करके अमरीका ने ऐसा ही प्रयास किया है। अमरीका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ उसका मजबूत सहयोगी बने। जबकि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। भारत अपने नुकसान-फायदे के हिसाब से तय करता है कि किस देश से कैसे रिश्ते रखने हैं। इसके विपरीत अमरीका उम्मीद करता है कि भारत उसकी हर बात का अक्षरश: पालन करे।

अमरीका चीन को रूस की तरह अपना दुश्मन मानता है। जबकि भारत चीन से अपने रिश्ते लगातार सुधार रहा है। अमरीका इस बात से खीझ रहा है कि भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ क्यों पिघल रही है। गलवान घाटी में चीन से हुई सशस्त्र झड़प के बाद रिश्तों में आई खटास कुछ हद तक मिठास में बदल गई है। दोनों देशों ने गलतफहमी को काफी हद तक दूर कर लिया है। समझौते की पालना के तहत दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख से न सिर्फ पीछे हट गई हैं, बल्कि सीमा पर संयुक्त सेनाएं गश्त कर रही हैं, ताकि गलवान घाटी की तरह सशस्त्र संघर्ष के हालात पैदा नहीं हों। दोनों देश लंबे अर्से से एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने से भी परहेज बरतते हुए द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर बल दे रहे हैं। भारत के चीन के साथ सुधरते रिश्ते और रूस से मजबूत होते द्विपक्षीय संबंध अमरीका को फूटी आंख भी नहीं सुहा रहे हैं। इन रिश्तों से तिलमिलाए अमरीका ने नया पैंतरा अपनाते हुए भारत को बदनाम करने के लिए अदाणी को मोहरा बनाया है। अमरीका का यदि बस चले तो पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ उकसाए। अमरीका ने आतंकवाद के नाम पर जो हथियार पाकिस्तान को दिए थे, उनका इस्तेमाल पाक आतंकी जम्मू-कश्मीर में कर रहे हैं।

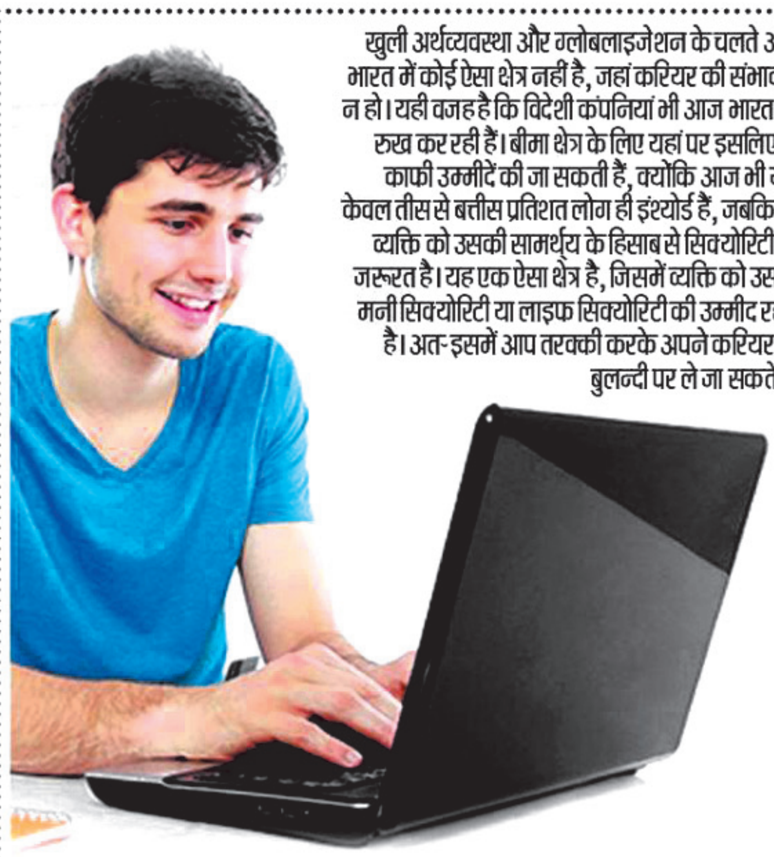

खुली अर्थव्यवस्था और ग्लोबलाइजेशन के चलते आज भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां करियर की संभावना न हो। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां भी आज भारत का रुख कर रही हैं। बीमा क्षेत्र के लिए यहां पर इसलिए भी काफी उम्मीदें की जा सकती हैं, क्योंकि आज भी यहां केवल तीस से बत्तीस प्रतिशत लोग ही इंश्योर्ड हैं, जबकि हर व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य के हिसाब से सिक्योरिटी की जरूरत है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें व्यक्ति को उसकी मनी सिक्योरिटी या लाइफ सिक्योरिटी की उम्मीद रहती है। अत: इसमें आप तरक्की करके अपने करियर को बुलन्दी पर ले जा सकते हैं।

इंश्योरेन्स
करियर की सिक्योरिटी

मार्केटिंग के इस दौर में हर काम को व्यवसाय की दृष्टि से देखा जा रहा है। यही कारण है कि पहले की अपेक्षा लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और तकरीबन हर व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान से निकल कर आगे की सोचने लगा है। अब हर किसी की चाहत रहती है कि वह एक स्टैण्डर्ड लाइफ जिए तथा हर तरह की सुविधाओं के अतिरिक्त उसके पास बैंक बैलेन्स और लाइफ सिक्योरिटी हो। ऐसे में इंश्योरेन्स सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जो व्यक्ति की दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति का दावा करता है। भारत में आज भी बहुत कम लोग बीमित हैं। यही कारण है कि आज विभिन्न कंपनियों के साथ बैंक भी इस क्षेत्र में अपने पैर पसार रहे हैं।

एक सर्वे के अनुसार, पिछले दस-बारह सालों में इंश्योर्ड यानी बीमित लोगों की संख्या दोगुनी के करीब हुई है अर्थात् भारत में इंश्योरेन्स सेक्टर का पदार्पण काफी पहले होने के बाद भी इस क्षेत्र में उतनी तरक्की नहीं हुई, जितनी कि वर्ष 2000 के बाद हुई और इस संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। सर्वे के मुताबिक कुल बीमित व्यक्तियों की संख्या में हर साल करीब दस प्रतिशत लोग नए जुड़ जाते हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले पन्द्रह वर्षों में भारत में करीब साठ प्रतिशत लोग बीमित हो सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव माइंड के हैं और पॉजीटिव सोच रखते हैं तो इंश्योरेंन्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं का भरोसा इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि आज भी देहातों में इंश्योरेन्स के प्रति लोगों में जागरुकता का खासा अभाव है। हालांकि जब से इंश्योरेन्स कम्पनियों ने छोटे शहरों और कस्बों की ओर रुख किया है, तब से काफी हद तक लोग इंश्योरेन्स को सही मायनों में समझने लगे हैं। लेकिन कम सर्विस और पहुंच के अभाव में अभी भी अधिकतर लोगों को इंश्योरेन्स की उतनी जानकारी नहीं है, जितनी होनी चाहिए। ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में इंश्योरेन्स बेचने और वहां के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने, उन्हें जागरुक करने के लिए सभी इंश्योरेन्स कम्पनियों को कर्मठ और योग्य लोगों की जरूरत रहती है। एक कम्पनी के ट्रेनिंग मैनेजर अजय कुमार बताते हैं कि 'एशियाई देशों में बहुत कम लोग इंश्योर्ड हैं, जबकि आज हर किसी को हाई रिस्क सेफ्टी की जरूरत है। एक सर्वे के अनुसार, हमारे देश में कुल बीस प्रतिशत लोग इंश्योर्ड थे। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब तीस से बत्तीस प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में इंश्योरेन्स सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। वर्ष 2000 तक भारत में काफी कम कम्पनियां इस सेक्टर से जुड़ी थीं, जबकि आज करीब 47 कम्पनियां लाइफ इंश्योरेन्स और जनरल इंश्योरेन्स से जुड़ी हैं, जिनमें लाइफ इंश्योरेन्स करने वाली कम्पनियों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा कुछ बैंक भी इस सेक्टर से जुड़ चुके हैं। इधर विदेशी कम्पनियों ने भी अपने व्यवसाय जमाने शुरू कर दिए हैं।

यदि आप भी मार्केटिंग से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो इंश्योरेन्स में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। इंश्योरेन्स सेक्टर में आपने कोई कोर्स किया हो अथवा नहीं, आप इस क्षेत्र में पदार्पण कर सकते हैं। यही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें आप बिना किसी स्पेशल कोर्स के भी कम से कम बतौर एजेन्ट आगे बढ़ सकते हैं। किसी कम्पनी में बतौर एजेन्ट काम शुरू करना पहली सीढ़ी है, लेकिन जैसे-जैसे बिजनेस यानी आपका टारगेट पूरा होता जाता है, वैसे-वैसे प्रमोशन भी होता जाता है। इस क्षेत्र में किसी भी पद पर प्रमोशन के लिए कम से कम एक साल मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति हर वर्ष प्रमोशन की सीढ़ी चढ़ सकता है।

दूसरे सेक्टरों की अपेक्षा इंश्योरेन्स सेक्टर एकदम भिन्न है। दूसरे सेक्टरों में जहां काम करने के घंटे निर्धारित होते हैं, इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती, बस आपको ग्राहक से अपनी डीलिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। इस सेक्टर में मेहनती और ईमानदार वर्कर्स की बेहद कद्र होती है। इसके लिए जो लोग इस क्षेत्र में अपनी कम्पनी के अधिकतम टारगेट या उससे अधिक का बिजनेस देते हैं, कम्पनी उनको तरह-तरह के आकर्षक और कीमती पुरस्कारों के अतिरिक्त देश-विदेश यात्रा का मौका देती है। इस क्षेत्र में लड़के -लड़कियां दोनों ही अपना भविष्य संवार सकते हैं।

स्कॉलरशिप – कुछ संस्थानों में एससी/एसटी तथा विकलांग और कुछ में पिछड़ा वर्ग को स्कॉलरशिप का प्रावधान है। संबंधित संस्थानों के अपने नियम हैं।

नौकरी के अवसर – इंश्योरेन्स एंड मैनेजमेंट के लोग इंश्योरेन्स, बैकिंग, शेयर बाजार तथा इंश्योरेन्स सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में नौकरी तलाश कर सकते हैं। जिन लोगों ने कोई कोर्स नहीं किया है, वे भी बतौर एजेन्ट या आईएसओ या बीडीओ या एक्जीक्यूटिव इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं।

एजुकेशन लोन – उम्मीदवार संस्थान की प्रवेश स्वीकृति के उपरान्त एजुकेशन लोन ले सकते हैं। लगभग सभी बैंक इसके लिए लोन प्रदान करते हैं। अधिकतम दस लाख तक का लोन मिल सकता है।

वेतन – इंश्यारेंस से संबंधित कोर्स करने वाले व्यक्ति को पन्द्रह हजार से पचास हजार (फ्रेशर की स्थिति में) तथा चालीस से दो लाख तक अनुभव और कोर्स के हिसाब से प्रतिमाह मिल जाते हैं।

करियर की अपार संभावनाएं
होटल मैनेजमेंट

होटल इंडस्ट्री सीधे तौर पर पर्यटन से जुड़ी है, परन्तु पर्यटकों का आना ही काफी नहीं होता, उन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं। उनकी गुणवत्ता के आधार पर ही पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसके अलावा बढ़ते औद्योगीकरण ने भी होटल व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने में मदद की है।

उदारीकरण के विस्तार में यह निश्चित है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती इस क्षेत्र को भी नई ऊंचाइयां देगी। पर्यटन और होटल इंडस्ट्री की जुगलबंदी से न सिर्फ देश में, बल्कि विदेश में भी रोजगार के बेशुमार अवसर सामने आ रहे हैं। भारत की होटल इंडस्ट्री के लिए इसे स्वर्ण युग ही कहा जाएगा और इसमें करियर बनाने वालों के लिए यह अपार संभावनाओं का समय है।

यह ग्लैमर से भरपूर ऐसा पेशा है, जिसमें अच्छे व प्रशिक्षित लोगों की फिलहाल कमी है। कहने को तो अन्य क्षेत्रों की भांति इसमें भी रोजगार तलाशने वालों की कमी नहीं है, किन्तु ऐसे लोगों की कमी है, जो इस पेशे के लिए जरूरी योग्यताओं पर खरे उतरते हों। भारत में बढ़ रही व्यावसायिक गतिविधियों का आलम यह है कि यहां के होटलों में कमरे खाली नहीं मिलते। एशिया प्रशांत क्षेत्र में होटल इंडस्ट्री के विकास के मामले में भारत का नम्बर चीन के बाद दूसरा है। एक अनुमान के अनुसार भारत में होटलों में 1, 10,000 से भी अधिक कमरे हैं। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल 41 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए और इस साल के रुझान को देखते हुए लगता है कि यह संख्या एक करोड़ को भी पार कर जाएगी। देशी भ्रमणकारियों की भी बड़ी संख्या है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, भारत के आंकड़े कहते हैं कि बिजनेस ट्रैवल के मामले में भारत का स्थान 18वां है और इस दशक में इसके पांचवें स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है। इन बातों के आईने में यह साफ नजर आता है कि होटल मैनेजमेंट कोर्स करके इस क्षेत्र में करियर बनाना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है।

होटल इंडस्ट्री में कैसा काम

होटल इंडस्ट्री में बतौर प्रशिक्षु कार्य करने से लेकर प्रबंधक बनने तक अनुभव व कार्य कौशल के कई चरणों से होकर गुजरना होता है। यह उम्मीदवार को तय करना पड़ता है कि किस विभाग के कार्य में उसकी विशेष रुचि है और आने वाले समय में उसका लक्ष्य क्या है। यह उसकी व्यक्तिगत योग्यता और व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा कि उसे कैसा अवसर मिल पाता है। वैसे किसी भी होटल में प्रबंधक व तमाम विभागों की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ पर नजर डालते हैं-

प्रबंधक

होटल के प्रबंधक इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं कि उनका होटल सुचारू रूप से चले और लाभ कमाए। महाप्रबंधक तो इस बारे में अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हैं कि वित्त की स्थिति ठीक रहे, कर्मचारी अतिथियों को स्तरीय सेवा प्रदान करने के साथ-साथ संस्थान के नियमों का भी पालन करें, हाउसकीपिंग ठीक हो, खाने का स्वाद व क्वालिटी ठीक हो, होटल की आंतरिक साज-सज्जा उच्च कोटि की हो इत्यादि। अलग-अलग विभागों के सहायक प्रबंधक अपने विभागों के कार्य पर निगरानी रखते हैं। बड़े होटलों में तो रेजिडेंट मैनेजर भी होते हैं।

फ्रंट ऑफिस

फ्रंट ऑफिस में बैठने वाले कर्मचारी होटल में आने वाले अतिथियों का स्वागत करते हैं। यहां रिसेप्शन होता है, सूचना डेस्क होता है, अतिथियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था देखने वाले होते हैं और बेलकैप्टन, बेल बॉय और डोरमैन होते हैं। ये लोग अतिथियों का सामान उनके कमरे में पहुंचवाने से लेकर उनको सूचनाएं भिजवाने का कार्य करते हैं।

फूड एंड बेवरेज (एफ एंड बी)

इस विभाग में तीन ईकाइयां होती हैं- पाकशाला यानी किचन, स्टीवर्ड विभाग और फूड सर्विस विभाग। इस विभाग के मैनेजर और कर्मचारी मिल कर इस विभाग की जिम्मेदारियों को निपटाते हैं। खाना बनाने से लेकर परोसने तक का काम यहां होता है। इससे जुड़ी हर चीज का रख-रखाव करना होता है।

हाउसकीपिंग

किसी भी होटल को उम्दा किस्म की देखभाल की जरूरत होती है। हाउसकीपिंग विभाग सभी कमरों, मीटिंग हॉल, बैंक्वेट हॉल, लाउंज, लॉबी, रेस्तरां इत्यादि की साफ-सफाई की जिम्मेदारी उठाता है। हर चीज करीने से दिखनी चाहिए, यह इस विभाग के काम करने का मूलमंत्र है। यह होटल का बेहद महत्त्वपूर्ण विभाग है और 24 घंटे काम करता है। इसमें पालियों में काम होता है।

मार्केटिंग विभाग

आज होटल में उपलब्ध सेवाओं व सुविधाओं की मार्केटिंग होटल मैनेजमेंट का अहम पहलू है। यह विभाग संभावित ग्राहकों की जरूरतों के लिहाज से पैकेज तैयार करता है और उन्हें बेचता है। इनकी काबिलियत का ही प्रत्यक्ष लाभ होटल को मिलता है। बेहतर पैकेजिंग से आकर्षित होकर जितने ग्राहक आते हैं, वे होटल को न सिर्फ बिजनेस देते हैं, बल्कि दूसरों को भी बताते हैं। इन सबके अलावा होटल में भी अन्य वे विभाग होते हैं, जो दूसरे संगठनों या कंपनियों में होते हैं, जैसे अकाउंट्स, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस इत्यादि। अब आपको तय करना है कि एक कामयाब करियर होटल मैनेजमेंट की चुनौतियों को स्वीकार करना है कि नहीं। इंडस्ट्री तो अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित लोगों को अवसर देने के लिए तैयार है।

पढ़ाई व प्रशिक्षण

अब सवाल यही उठता है कि होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए कहां से क्या पढ़ा जाए तथा कैसा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए? इस विषय में पढ़ाई करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर पीजी कोर्स तक उपलब्ध हैं, जिन्हें अलग-अलग संस्थान कराते हैं। होटल मैनेजमेंट कोर्स कराने वाले सरकारी संस्थान हैं और निजी संस्थान भी। सरकारी संस्थानों में अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिला लेते हैं और निजी संस्थानों में साक्षात्कार व अंक प्रतिशत के आधार पर चयन किया जाता है। निजी संस्थानों में दाखिले के लिए अभ्यर्थी को अपनी सुविधा और सामर्थ्य के मुताबिक संस्थान का चयन करना चाहिए। सरकारी संस्थान बुनियादी सुविधाओं के मामले में तो बेहतर हो सकते हैं, किन्तु उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई तरीका नहीं है। फिर भी सरकारी तंत्र के अपने लाभ हैं। बहरहाल, निम्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं –

- बेकरी एंड कन्फेक्शनरी/होटल रिसेप्शन एंड बुक कीपिंग/रेस्तरां एंड काउंटर सर्विस में एक वर्षीय डिप्लोमा
- होटल मैनेजमेंट में तीन वर्षीय डिप्लोमा
- होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी में चार वर्षीय स्नातक डिग्री
- होटल मैनेजमेंट में तीन वर्षीय बीएससी
- हॉस्पिटेलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में तीन वर्षीय बीए
- इंटरनेशनल होटल्स में दो साल का पीजी डिप्लोमा
- हॉस्पिटेलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में दो साल की एमएससी
- होटल एंड केटरिंग मैनेजमेंट में छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स

योग्यता

इन पाठ्यक्रमों को करने के लिए किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं/ 12वीं या स्नातक होना जरूरी है। 12वीं में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ी होनी चाहिए।

नौकरी के अवसर

होटल मैनेजमेंट कोर्स करने वालों के लिए कई विकल्प हैं-

- होटल एवं हॉस्पिटेलिटी उद्योग में मैनेजमेंट प्रशिक्षु।
- होटलों में किचन मैनेजमेंट या हाउसकीपिंग मैनेजमेंट।
- एयरलाइन केटरिंग एंड केबिन सर्विसेज।
- होटल एवं अन्य सर्विस सेक्टर में गेस्ट या कस्टमर रिलेशन एक्जिक्यूटिव।
- फास्ट फूड चेन। ल्लरिसोर्ट मैनेजमेंट।
- क्रूज शिप होटल मैनेजमेंट, ल्लगेस्ट हाउसेज।
- हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड केटरिंग।
- रेलवे या बैंक या बड़े संस्थानों में केटरिंग या कैंटीन।
- स्वरोजगार

वेतन

कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी के तमाम अवसर हैं, जिनमें अपनी रुचि और दक्षता के आधार पर करियर बनाया जा सकता है। इनमें शुरुआती स्तर पर 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नियमित नौकरी मिल सकती है। जैसे-जैसे अनुभव बढ़ेगा और कुशलता आएगी, वेतन उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा, जो लाखों में भी हो सकता है।

व्यक्तिगत गुण

इस पेशे में रुचि रखने वालों के लिए सबसे जरूरी तो यह है कि उनका व्यक्तित्व आकर्षक हो। उनमें ऐसी बात हो कि उससे उनका दोस्ताना रवैया झलके। उनके करीब आते ही सामने वाला इस बात के लिए न हिचके कि वह उनसे मदद मांगे कि नहीं। व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि उनसे शालीन खुलेपन की सुगंध आए। वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें, न कि टालमटोल और दूसरों पर डालने की प्रवृत्ति के मारे हों। काम को मिलजुल कर करने का हौसला रखते हों तो क्या कहने। किसी भी मसले पर तरतीब से सोचने की क्षमता हो और प्रशासनिक दक्षता भरपूर हो। इनके अलावा स्वस्थ हों और किसी भी समय कार्य करने के लिए तत्पर हों। आत्म-विश्वास और हर काम की बारीकियों को समझने और उसे अपेक्षानुसार करने का गांभीर्य भी होना चाहिए उन सबमें, जो इस स्वागत सत्कार के संसार में अपनी पहचान बनाने की हिम्मत रखते हों। बताने की जरूरत नहीं कि होटल में आने वाला हर गेस्ट खास होता है। लिहाजा उसकी हर बात को गंभीरता से लेना होता है और उसे समझदारी से संभालना होता है। काम के दबाव में भी आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, ऐसा इंडस्ट्री के पंडित कहते हैं। यदि ऐसा कुछ आप में है तो कोई वजह नहीं कि कोई आपको नकार दे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

राज्यसभा में विपक्ष पर भड़के सभापति धनखड़

नई दिल्ली। गौतम अदाणी के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है और संसद का शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। बुधवार को भी विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बुधवार को विपक्ष के रवैये पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि उच्च सदन के सदस्यों को सदन की परंपरा का पालन करने की जरूरत है। दरअसल बुधवार को विपक्ष के कई सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। जब उच्च सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरा हमेशा इस बात पर जोर होता है कि उच्च सदन की स्थापित परंपराओं का पालन किया जाए। राज्यसभा सभापति के फैसले का सम्मान करने की जरूरत है। सदन के नियम 267 (स्थगन प्रस्ताव) के तहत इतने कई प्रस्ताव मिले हैं। बीते 30 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो इस दौरान कई सरकारें और प्रशासन सत्ता में आए, लेकिन कभी भी प्रस्तावों की संख्या एकल अंक से ज्यादा नहीं रही।

मुझे सीएम बनने की लालसा नहीं, शिंदे ने साफ किया रुख

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बुधवार को सीएम पद को लेकर चल रही चर्चाओं को विराम दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में सीएम बनने की लालसा नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। सरकार बनाते समय मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं चट्टान की तरह साथ खड़ा हूं। भाजपा की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमें मान्य होगा। भाजपा का सीएम मुझे मंजूर है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछले ढाई साल में पीएम मोदी और अमित शाह ने मेरा पूरा सहयोग किया। अमित शाह और पीएम मोदी ने बालासाहेब ठाकरे के एक आम शिवसैनिक को सीएम बनाने के सपने को पूरा किया है। वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मुझे मुख्यमंत्री बनाया और बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं रोने वालों और लड़ने वालों में से नहीं हूं। मैं भागने वाला नहीं समाधान करने वाला व्यक्ति हूं।

सीएम के नाम के ऐलान में देरी पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को विपक्ष से सवाल किया कि अगर निर्णय हो गया तो उन्हें देवेंद्र फडणवीस के नाम को घोषणा करने से कौन रोक रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर देवेन्द्र फडणवीस का नाम फाइनल हो गया है तो जल्दी घोषणा करें; आपको क्या रोक रहा है? आप महाराष्ट्र की जनता से किए गए वादों से उन्हें वंचित क्यों कर रहे हैं, उन्हें दूर क्यों रख रहे हैं और महाराष्ट्र के स्टीयरिंग संकट को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? भाजपा पर वार करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने ने कहा कि वे सत्ता के लिए भूखे हैं। चुनाव आए कई दिन हो गए हैं और अभी तक नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। इसके अलावा, उन्होंने सवाल किया कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल विजेता घोषित करने के लिए निकाले गए और गिने गए वोटों की संख्या में छेड़छाड़ करने के माध्यम के रूप में किया जा रहा है।

राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का आह्वान किया। मीडिया से बात करते हुए राउत ने विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल करने के बावजूद सरकार बनाने में महायुति गठबंधन की असमर्थता की आलोचना की। उन्होंने कहा, उन्हें (महायुति) भारी बहुमत मिला है, फिर भी उन्होंने न तो मुख्यमंत्री पर फैसला किया है और न ही सरकार बनाई है। जब हम सरकार बनाने के लिए आशान्वित थे, तो हमें बताया गया कि अगर हम 26 नवंबर तक ऐसा करने में विफल रहे, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। महायुति गठबंधन, जिसने 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 230 से ज्यादा सीटें जीती हैं, ने अभी तक राज्य के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, गठबंधन ने मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला कर लिया है, लेकिन भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच विभागों के बंटवारे पर चर्चा के कारण घोषणा में देरी हो रही है।

सीएम पद पर खींचतान के बीच दिल्ली बुलाए गए फडणवीस

नईदिल्ली। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस के बीच देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात अमित शाह और भाजपा के अन्य बड़े नेताओं से हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि फडणवीस का महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि, एकनाथ शिंदे की नाराजगी भाजपा की परेशानी को बढ़ा रही है। वहीं, शिवसेना ने बुधवार को कहा कि एकनाथ शिंदे कभी भी उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। शिंदे सेना के एक नेता ने कहा कि 20 नवंबर के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति की प्रचंड जीत केवल एकनाथ शिंदे के कारण थी। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा गया था। वह मुख्यमंत्री के रूप में वापसी के हकदार हैं। इन घटनाक्रमों के बीच भाजपा की केंद्रीय पर्यवेक्षक टीम अगले दो दिनों में मुंबई आएगी और इस दौरान देवेंद्र फडणवीस को नेता चुनने की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

अदाणी और संभल मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा स्थगित

नईदिल्ली। विपक्षी सांसदों के लगातार विरोध के बीच, लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया और गुरुवार, 28 नवंबर को फिर से बैठक होगी। वहीं, विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण संसद के उच्च सदन की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नारेबाजी के साथ शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने अडानी रिश्वत मामले और संभल हिंसा को लेकर हंगामा किया। संसद का शीतकालीन सत्र 2024 सोमवार, 25 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में अपना पारंपरिक संबोधन दिया, जिसमें सभी सांसदों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया गया।

लोकसभा की कार्यवाही

विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक बुधवार को एक बार के स्थगन के बाद पुन: शुरू होने के करीब 10 मिनट के अंदर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और अदाणी समूह से जुड़े मामले को उठाने का प्रयास करने लगे, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने संभल की घटना को उठाने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू कराया।

इस बीच, कांग्रेस और सपा के कई सदस्य आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अरुण गोविल का उल्लेख करते हुए कहा कि वह पहली बार प्रश्नकाल में प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे में सदन की कार्यवाही चलने दी जाए। हालांकि, हंगामा नहीं थमा और विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। दोपहर 12 बजे निचले सदन की बैठक फिर शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि, शोर-शराबे के कारण सदन की बैठक दिनभर के स्थगित कर दी गई।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री की जांच के लिए कानूनों के बारे में बात की। उन्होंने अपमानजनक सामग्री की जांच के लिए कानूनों के संबंध में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सदस्य अरुण गोविल द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया।

राज्यसभा की कार्यवाही

कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग को लेकर बुधवार को राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें अदाणी, मणिपुर हिंसा, संभल हिंसा और दिल्ली में अपराध के बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कुल 18 नोटिस मिले हैं। उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए।

जी सी चंद्रशेखर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, नीरज डांगी और राजीव शुक्ला सहित कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने अन्य प्राधिकरणों के साथ मिलीभगत से अदाणी समूह के कथित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं सहित अन्य कदाचारों की जांच के लिए, जेपीसी के गठन के लिए नोटिस दिए थे। सभापति धनखड़ ने सभी नोटिस अस्वीकार करते हुए कहा कि सदस्य इन मुद्दों को अन्य प्रावधानों के तहत उठा सकते हैं। इसके तत्काल बाद कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया।

अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है : राहुल गांधी

अडानी रिश्वत मामला बुधवार को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह गूंजा, जब दो वरिष्ठ वकीलों ने अडानी समूह के अध्यक्ष के खिलाफ अमेरिकी आरोपों में छेद करने का प्रयास किया, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कई विपक्षी नेताओं द्वारा रिश्वत मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिए जाने के बाद संसद में हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया और अन्य सभी कामकाज निलंबित कर दिए गए।

संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी के लिए अपना आह्वान दोहराया और कहा कि उद्योगपति अमेरिकी अभियोजकों द्वारा उल्लिखित आरोपों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अडानी आरोप स्वीकार करेंगे? जाहिर है, वह आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। छोटे-छोटे आरोपों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों करोड़ का आरोप लगाया गया है, उन्हें जेल में होना चाहिए। सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि तथ्य यह है कि दो अभियोग दायर किए गए हैं, एक न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अटॉर्नी द्वारा और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा। इसलिए, वे स्पष्ट रूप से अमेरिकी अदालत के समक्ष ये तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। मूल मुद्दा यह है कि ये अभियोग भारत के कारोबारी माहौल के संबंध में किस तरह का संदेश भेजते हैं। उन्होंने कहा कि नंबर दो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड क्या कर रहा था? यदि अमेरिकी नियामक को अभियोग दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। यदि आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को याद करें, तो अडानी समूह के संबंध में मुद्दे न केवल सार्वजनिक डोमेन में थे, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस पर आंदोलन किया जा रहा था या फैसला सुनाया जा रहा था। तो सवाल यह है कि नियामकों को विनियमित कौन करेगा? इसलिए, इसमें बड़े मुद्दे शामिल हैं और इसीलिए हम संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहे हैं।

अदाणी मामले में कांग्रेस आग से खेल रही, यह देशहित में नहीं, कांग्रेस पर भड़के वरिष्ठ वकील जेठमलानी

नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने गौतम अदाणी मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जेठमलानी ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला है और कांग्रेस बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगा रही है। जेठमलानी ने ये भी कहा कि जिस न्याय विभाग ने अदाणी समूह पर आरोप लगाए हैं, उसे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खारिज कर चुके हैं।

अदाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी न्यायालय में लगाए गए आरोपों पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि न्याय विभाग (डीओजे) एक तमाशा है, लेकिन कांग्रेस कभी इस पर ध्यान नहीं देती। अमेरिकी न्याय विभाग बहुत ही जल्दबाजी में काम कर रहा है। इसके समय पर गौर किया जाना चाहिए क्योंकि ये (डेमोक्रेट सरकार) अब लगभग सत्ता से बाहर हो चुके हैं। यही वजह है कि वे सबकुछ तबाह करने पर आमादा हैं। गौतम अदाणी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की और शायद ये डेमोक्रेट सरकार को पसंद नहीं आया। यह मामला पिछले काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब बहुत जल्दबाजी की गई और अभियोग में भी अस्पष्टता है और कोई ठोस सबूत भी नहीं है।

महेश जेठमलानी ने कहा कि, अदाणी के खिलाफ जो अभियोग लाया गया है, उसकी टाइमिंग भी संदिग्ध है। यह चुनाव से ठीक पहले और संसद सत्र की पूर्व संध्या पर सामने आया है। अदाणी के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है और अभियोग में कोई अपराध भी आरोपित नहीं किया गया है। अभियोग में भी भारत में किसी भी रिश्वतखोरी की बात नहीं है। यह केवल इतना कहता है कि रिश्वत देने की साजिश हुई थी, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। भारत में विदेशी भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यह सारा शोर कांग्रेस पार्टी ने मचाया है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा कौन सा सबूत है जो साबित करता है कि सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की कोई साजिश थी? कांग्रेस पार्टी एक भारतीय उद्योग समूह के खिलाफ अभियोग पर आंख मूंदकर भरोसा कर रही है, जिसने विदेशों में भारत के लिए कई उपयोगी व्यवसाय किए हैं। कांग्रेस इस अभियोग को बहुत ज्यादा पढ़ रही है और वे इसे पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि, यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्हें (कांग्रेस) महाराष्ट्र चुनाव में अभी-अभी हार का सामना करना पड़ा है। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में बेशक सफल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जहां उन्हें जीत की उम्मीद थी, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन सिर्फ अदाणी और मणिपुर के मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जबकि ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि इन मुद्दों पर राजनीति करना देश हित में नहीं है और कांग्रेस आग से खेल रही है।

खेल
प्रमुख समाचार

जसप्रीत बुमराह फिर टेस्ट क्रिकेट के नंबर-1 गेंदबाज बने

दुबई। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। बुमराह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया था और कुल आठ विकेट झटके थे। बुमराह को उनके प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। बुमराह ने इस मैच में रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में कप्तानी की थी और टीम ने उनके नेतृत्व में जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी।

बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबाडा को पीछे छोड़ा और एक कैलेंडर वर्ष में दूसरी बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के शुरू होने से पूर्व बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में रबाडा और जोश हेजलवुड के बाद तीसरे स्थान पर थे। पहले टेस्ट मैच में दमदार प्रदर्शन का फायदा बुमराह को मिला और वह एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गए। श्रीलंका के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की जीत के तेज गेंदबाजी की अगुआई कर रहे रबाडा दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पांच विकेट लेने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड तीसरे स्थान पर हैं।

भारत को ऑस्ट्रेलिया पर मिली 295 रनों की जीत में अहम योगदान देने वाले यशस्वी जायसवाल ने भी रैंकिंग में छलांग लगाई है। यशस्वी बल्लेबाजों की रैंकिंग दो स्थान के सुधार के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उनसे आगे फिलहाल इंग्लैंड के जो रूट हैं। यशस्वी की रेटिंग अंक 825 है जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है। यशस्वी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 161 रनों की पारी खेली थी। हालांकि, वह पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके थे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में आई तेजी! सेंसेक्स 230 अंक चढ़ा

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को तेजी लौट गई और दोनों प्रमुख इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। अदाणी ग्रुप के शेयरों और इंडेक्स में हैवी वेटेज रखने वाले एचडीएफसी बैंक के शेयर में तेजी से बाजार 27 नवंबर को चढ़कर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बुधवार (27 नवंबर) को 100 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 80,121.03 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 80,511.15 अंक तक चढ़ गया था। अंत में सेंसेक्स 0.29% या 230.02 अंक चढ़कर 80,234.08 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 0.33% या 80.40 अंक की बढ़त लेकर 24,274.90 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की 25 कंपनियों के शेयर हरे जबकि शेष 25 के शेयर लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स आज की तेजी के साथ पिछले तीन सप्ताह के हाई लेवल पर पहुंच गया है।

एक ही कंपनी दे सकेगी सारे इंश्योरेंस कवर

नईदिल्ली। सरकार संसद के चालू सत्र में बीमा कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की योजना बना रही है। इनमें यूनिफाइड लाइसेंस और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव शामिल है। यूनिफाइड लाइसेंस एक कम्पोजिट लाइसेंस है, जिससे बीमा कंपनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकेंगी। वर्तमान में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ कवर जैसे उत्पाद नहीं बेच सकतीं, जबकि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ और मरीन इंश्योरेंस बेचने की अनुमति है। नए लाइसेंस से इस जटिलता को दूर किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 100% तक बढ़ाने का उद्देश्य अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना और देश में बीमा उत्पादों की पहुंच को बढ़ाना है।

तेल, चायपत्ती के साथ सब्जियों ने बिगाड़ा किचन का बजट

नईदिल्ली। रसोई का बजट महंगाई की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सब्जियों के साथ-साथ आटा, मैदा, ब्रेड, रिफाइंड तेल और चायपत्ती की बढ़ती कीमतें घर के किचन का खर्च बढ़ा रही हैं। कई चीजों की कीमत पिछले साल के मुकाबले दोगुनी तक हो गई है। आटे के 10 किलो के पैकेट की कीमत में 20-30 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि ब्रेड के प्रति पैकेट में 5 रुपए तक बढ़ गए हैं। चायपत्ती के दाम में प्रति किलो 50 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। रिफाइंड तेल की कीमत में पिछले दो महीनों में प्रति लीटर 15 रुपए का उछाल आया है। आटा कारोबारी राजीव गोयल ने बताया कि बाजार में गेहूं की कमी आटे की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण है। पिछले साल केंद्र सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम से राहत मिली थी लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। इसके चलते आटे की कीमत में प्रति किलो 3-4 रुपए का इजाफा हुआ है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि गेहूं की आपूर्ति बढ़ाई जाए।

पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री रिकॉर्ड 44.9 लाख इकाई पर

नई दिल्ली। देश में पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) की बिक्री जुलाई-सितंबर में मामूली बढ़कर 44.9 लाख इकाई रही। यह किसी एक तिमाही में अबतक की सबसे ज्यादा बिक्री है। बाजार शोध कंपनी इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक, पर्सनल कंप्यूटर बाजार में एचपी 29 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ अगुवा रही। हालांकि, उसकी बिक्री सालाना आधार पर 1.5 प्रतिशत घटकर 13 लाख इकाई रही। पर्सनल कंप्यूटिंग उपकरण पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) की तिमाही रिपोर्ट में कहा गया, ''भारत के पारंपरिक पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) बाजार (डेस्कटॉप, नोटबुक और वर्कस्टेशन सहित) 2024 की तीसरी तिमाही में अबतक की सर्वाधिक 44.9 लाख इकाइयों की बिक्री हुई। यह सालाना आधार पर 0.1 प्रतिशत अधिक है।

समावेशी विकास के लिए सहकारी आंदोलन जरूरी, तभी कम होंगी आर्थिक दरारें

शाजी केवी

साझा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, समावेशी विकास रणनीति 'सहकार से समृद्धि' के देश में अब तक काफी कारगर नतीजे सामने आए हैं। स्वतंत्रता से पहले के दौर में अगर हम भारत में सहकारिता आंदोलन की उत्पत्ति को देखें, तो पाएंगे कि इसकी शुरुआत किसानों की गरीबी कम करने की चुनौती से हुई थी, जिसका मुख्य कारण बार-बार पड़ने वाला सूखा और साहूकारों की सूदखोरी प्रवृत्ति था। एनएएफआईएस, 2021-22 के अनुसार ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के माध्यम से केंद्र सरकार की निरंतर और लक्षित वित्तीय समावेशी पहलों के कारण, ग्रामीण परिवारों की साहूकारों और जमींदारों पर निर्भरता अब घटकर मात्र 4.2 प्रतिशत रह गई है।

भारत में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली प्रारंभिक शक्तियां भले ही अब कमजोर पड़ रही हों, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस समय कई नई और जटिल उभरती चुनौतियां हैं, जिनके लिए सहकारी आंदोलन को नई दिशा और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इन नई चुनौतियों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर एक कुशल ग्रामीण आपूर्ति शृंखला हासिल करना, स्थायी आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति को कम करना, कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि उत्पादकता तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले प्रयासों को बढ़ाना और डिजिटल क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाना शामिल है। सहकारी संस्थाओं के लिए मददगार नीतियां बनाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 'सामाजिक विकास में सहकारी समितियों पर रिपोर्ट' (2023) से जानकारी प्राप्त करना उपयोगी हो सकता है,

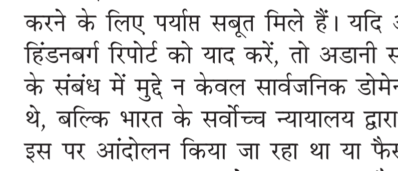

जो इस बात पर जोर देती है कि 'सहकारी समितियां बाजार संबंधी विफलताओं से निपटने, हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाकर सतत विकास को सहारा देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं'।

भारत के सहकारी क्षेत्र में दूध और चीनी के क्षेत्रों में मिली अपार सफलता केवल एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व को ही प्रमाणित करती है। इसका एक और सफल उदाहरण भारत की सबसे पुरानी श्रमिक सहकारी संस्था-उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी का है, जो इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रही है। सहकारिता के दो खास पहलू हैं, जिनमें पहला है, 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' का महत्व। जब उरालुंगल को एक सड़क परियोजना हेतु लिए गए भारी कर्ज की किश्तें चुकानी थीं, तो उसने 38 प्राथमिक सहकारी समितियों का एक संघ बनाया और उनकी मदद से यह भारी राशि जुटा सकी;?दूसरा, निजी फर्मों के विपरीत, संकट की स्थिति में एक श्रमिक सहकारी समिति द्वारा रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

नाबार्ड सहकारी समितियों को एक-दूसरे के तुलनात्मक लाभों से लाभान्वित करने की सुविधा प्रदान कर इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' को बढ़ावा दे रहा है। इस पहल में वित्तीय पक्ष से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु-सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के मौजूदा बैंक खातों को विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में समेकित करना और उन्हें एक केंद्रीकृत जिला/राज्य सहकारी के तहत रखना होगा, जिससे सहकारी प्रणाली के संसाधन प्रणाली के भीतर ही बने रहेंगे।

भविष्य में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में नीतिगत तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। हाल के वर्षों में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दुग्ध क्षेत्र की तर्ज पर इन तीनों वस्तुओं के लिए अधिक से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन और एक एकीकृत आपूर्ति शृंखला मदद कर सकती है। उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे को देखते हुए बागवानी फसलों की बिक्री से होने वाले लाभों के मद्देनजर विशेष रूप से बहु-राज्य सहकारी समितियों को उत्पादकों का एक व्यापक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन ने राजनाथ व मंडाविया से की मुलाकात

बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सेना की भूमि के हस्तांतरण में तेजी लाने की मांग

नई दिल्ली/रायपुर। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और हवाई अड्डे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए बिलासपुर हवाई अड्डे से सटी सेना की भूमि के

हस्तांतरण पर चर्चा की। परियोजना के महत्व पर बोलते हुए, मंत्री तोखन साहू ने कहा, बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार और आधुनिकीकरण से न केवल क्षेत्र के लिए हवाई संपर्क बढ़ेगा बल्कि रोजगार, व्यवसाय और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की हमारी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंत्री तोखन साहू ने मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार उस भूमि के बदले आवश्यक राशि जमा करने के लिए तैयार है, जो पहले सेना को दी गई थी लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है। सेना की भूमि का हस्तांतरण और उसके बाद बिलासपुर हवाई अड्डे का विस्तार छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी बढ़ाने, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और समग्र आर्थिक संभावनाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुलाकात के दौरान ने रक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि वह संबंधित अधिकारियों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और हस्तांतरण के लिए आवश्यक औपचारिकताओं और शेष प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दें, ताकि हवाई अड्डे के विस्तार को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाया जा सके।

'खेलो इंडिया' के तहत छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना के विकास की रखी मांग

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से

मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से बिलासपुर और मुंगेली जिलों में खेल अधोसंरचना को उन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा की। बता दें कि मंत्री तोखन साहू ने बैठक के दौरान स्थानीय युवाओं को खेलों से जोड़ने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भावना को प्रेरित करने के लिए खेल अवसंरचना में निवेश के महत्व पर जोर दिया। मंत्री तोखन साहू ने इससे पहले केंद्रीय मंत्री मंडाविया को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने बिलासपुर और मुंगेली जिलों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और खेल प्रेमियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर प्रकाश डाला था। मंत्री तोखन साहू ने बताया कि खेल के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं और अत्याधुनिक खेल सुविधाएं स्थापित करने से युवाओं को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे एथलीटों की नई पीढ़ी तैयार होगी। श्री साहू ने कहा कि हमारे युवाओं की अद्भुत क्षमता को सामने लाने के लिए जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना में सुधार करना महत्वपूर्ण है। सही समर्थन और सुविधाओं के साथ, छत्तीसगढ़ उभरती हुई खेल प्रतिभाओं का केंद्र बन सकता है और 'खेलो इंडिया' के तहत यह पहल उस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बाबू भैया की कलम से

मतपत्र या ईवीएम ? कांग्रेस ने कहा करेंगें भारत यात्रा

प्रत्येक चुनावों के परिणाम के बाद इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर प्रश्न चिन्ह लगता ही लगता है। हार ही मशीन पर उंगली उठाने को मजबूर करती है। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि इस बात से इनकार करते हुए इसे रोकने से साफ मना किया अर टिप्पणी भी की,कि जहां हार होती है वहां ईवीएम में गड़बड़ी और जहां जीत गए वहां ईवीएम ठीक कैसे हो सकती है। जनता में तो यह बात हर बार शंका के रूप में चर्चा में सामने आती ही है। अब तो अनेक सामाजिक व राजनैतिक पार्टी ने दबे जुबान में ईवीएम के परिणाम पर शंका जाहिर की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तो खुले तौर पर बहुत साफ शब्दों में मांग खड़ी करते हुए कहा भी है कि फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। इसके लिए भारत जोड़ो अभियान की तर्ज पर नया अभियान चलाया जाएगा। मतपत्रों से चुनाव की मांग तब उठाई गई है,जब अभी हाल झारखंड व महाराष्ट्र में चुनाव तथा अनेक रज्यों में उपचुनाव हुए हैं। कुछ सीटों पर कांग्रेस आई जरूर लेकिन सामान्य रूप से चल रही जनहवा के कहीं कहीं विपरीत परिणाम देख कर कांग्रेस ने यह बात उठाई है। कार्यकर्ताओं व नेताओं के फीडबैक एकदम फेल होने से ही यह शंका उपजी है। 19-20 का फर्क समझ में आता है ,पर जिस तरह के परिणाम महाराष्ट्र में आये पार्टी के आंतरिक सर्वे में उसकी दूर दूर तक संभावना नहीं थी।कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यह कैसे संभव है कि एक जगह मशीन ठीक है और दूसरी जगह गलत ? इस टिप्पणी पर ईवीएम के विरोधियों ने कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये कि एक जगह सही एक जगह गलत का जवाब यह है कि जो भी गड़बड़ी होती है उसी राज्य में होती है जहां के परिणाम से केंद्र की सरकार को झटका लग सकता है।सरकार कमजोर हो गई का संदेश जा सकता हो। झारखंड में शायद इसीलिए छोड़ दिया गया ताकि कोई महाराष्ट्र के परिणाम पर उंगली न उठा सके। तर्क तो तर्क है। चर्चा चल पड़ी कि ऐसी गड़बड़ी है जरूर जो किसी के समझ में नहीं आ रही कि ,यह हो कैसे रहा है ? बहरहाल किसी आम आदमी या किसी सामाजिक संगठन ने नहीं बल्कि आज के दिन देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खरगे ने यह बात जोरशोर से उठाई है कि चुनाव मतपत्रों से होना चाहिए,इसके लिए फिर भारत जोड़ो यात्रा की तरह यात्रा अभियान चलाया जाएगा देश भर में इस बात को बहस का मुद्दा बन कर जनता की राय भी सामने आ जाएगी। परिणामों से बुद्धिजीवी वर्ग के साथ सर्वे करने वाली मीडिया भी हतप्रभ है कि सर्वे इस कदर फेल कैसे हो रहे हैं। मीडिया हतप्रभ जरूर है पर बात को मुद्दा बनाने से उसे परहेज क्यों है ,यह समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ईवीएम समर्थक द्वारा अपने तर्कों में साफ कहा जाता है कि ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ किसी हालत में संभव ही नहीं है। कैसे हो सकती है जब परिणाम के दौर में सभी दलों के लोग मौजूद होते हैं और सबके सामने मशीने दिखाई जाती हैं। सील दिखाई जाती हैं। स्ट्रांग रूम में पहरे होते हैं। सभी दलों की नजर लगी होती है। इस तर्क के जवाब में तर्क आता है कि ,यह एआई का युग है ,आवाजें व चेहरे की कॉपियां हो जातीं हैं। बड़ी बड़ी ठगी हो जाती है, तो इस आधुनिक युग में इलेक्ट्रानिक मशीनों में भी कुछ भी किया जाना संभव है। अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें लोग ईवीएम के पक्ष -विपक्ष में सामने लाते रहते हैं। चुनाव आयोग सबूत माँगता है। सबूत कोई प्रस्तुत नहीं करता। अभी तक तो नहीं ही कर पाया है। अखबारों के बयानों तक सीमित है। चर्चा भी हर चुनाव के बाद ही होती है। पिछली बार भूपेश सरकार की पूरी संभावना होने के बाद भी छतीसगढ़ में वापसी ना होना। हरियाणा में हवा के विपरीत परिणाम। अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह माहौल के विपरीत परिणाम ने फिर इस मुद्दे को बहस में बदल दिया है। संजय राउत ने तो अभी हाल के परिणाम के दिन ही कह दिया था कि ये परिणाम जनता जनार्दन के नहीं है। जनता के मूड के विपरीत परिणाम है। मैं इस परिणाम को नहीं मानता। अब तो इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रमुख खरगे ने व्यापकता देदी है। अब पूरे भारत में इसका हल्ला मचेगा,जनता के बीच मशीनों पर शंका जाहिर की जाएगी। चर्चाएं-बहस चलेगी, सबमें तो शंका है लेकिन किन्हीं अखबारों व टीवी में भी शायद चर्चा हो जाए। जनता जनार्दन इस विषय पर व्यापकता से सोचे। सच क्या है यह समझने का प्रयास करे। प्रचार प्रसार व राजनीति के इस कांग्रेसी दांव का जवाब भाजपा नेतृत्व क्या व कैसे देगा यह समय पर पता चलेगा। लेकिन एक बात जनसाधारण के मन में है जरूर कि , जब ईवीएम समर्थक कहते है कि सब सही है ,कोर्ट ने भी इसी लाइन में अपना फैसला दिया है, तो फिर क्यों ना एक बार मतपत्रों से ही चुनाव करा दिया जाए और सदा सदा के लिए इस विवाद को समाप्त कर दिया जाए। साबित करवा दिया जाए कि मतपत्र के चुनाव भी हमारे पक्ष में ही हैं। ईवीएम पूरी तरह पाक साफ हैं और अब इस पर कभी चर्चा नहीं होगी।

प्रदेश में महिलायें असुरक्षित, सरकार के नियंत्रण से बाहर कानून व्यवस्था

भाजपा सरकार के राज में अपराधी बेलगाम, आम आदमी असुरक्षित

रायपुर। प्रदेश में महिलायें असुरक्षित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राजधानी में फिर एक बार गैंगरेप हो गया। पिछले तीन दिन से रायपुर में रोज दुराचार की घटना हुई है। मनेन्द्रगढ़ में तीन शिक्षकों, एक वनकर्मी ने नाबालिक छात्रा के साथ गैंगरेप की घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में डीएफओ ने महिला रेंजर से दुष्कर्म किया। सरकार के नियंत्रण से कानून व्यवस्था बाहर हो चुकी है। जिस राजधानी में एक साल पहले तक महिलायें रात को 11 बजे भी बेखौफ हो कर अपने घरों से बाजार चली जाती थी, वहीं पर शाम को 6 बजे के बाद आम आदमी घर से निकलने में डरता है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के क्षेत्र में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मुख्यमंत्री के गृह ब्लाक में नाबालिक स्कूली छात्रा से गैंगरेप हुआ, आरोपी अब तक फरार हैं। कोरबा में स्कूल छात्रा से 5-5 लोगों ने दुष्कर्म किए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में अपराधी बेलगाम हो गये है। आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। पुलिस दावा करती है रायपुर में चाकूबाजी की घटनाओं में 40 प्रतिशत कमी हुई है जबकि पुलिस के आंकड़ों में ही धारदार नुकीले हथियार से घायल लोगों की संख्या चाकूबाजी से चार गुना अधिक है। चाकूबाजी घटना को कम दिखाने पुलिस चाकू के बजाय नुकीले धारदार हथियार से हमला लिखती है, दावा करती है चाकूबाजी की घटना कम हो गयी है। रायपुर शहर में नवंबर माह में अभी तक 23 से अधिक हत्याएं हुई है। प्रदेश का हर नागरिक डरा हुआ है। महिलायें असुरक्षित है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ गयी है। एक ही दिन में राजधानी के विधानसभा के पास आमासिवनी में शराब दुकान के सामने दो-दो हत्याये हुई, पुरानी बस्ती थाने के चंद कदमों की दूरी पर पेट्रोल डालकर एक युवक को जिंदा जला दिया गया, तेलीबांधा में गवाह को धमकाने अपराधियों ने हमला कर दिया, दिनदहाड़े गोलियां चल रही है, गैंगवार हो रहे हैं। दीवाली के दिन ही राजधानी रायपुर में 9 हत्या हुई, दुर्ग में 4 हत्याएं हुई। रायपुर में रोज हत्याएं हो रही है लेकिन यह सरकार आपराधिक घटनाओं को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। राजधानी में 11 माह में 5 गोली कांड हुआ, अंतरराज्यीय गैंगस्टर रायपुर तक पहुंच गये।

डे-एनयूएलएम में तीन महीनों की कार्यवृद्धि साव से मिलकर कर्मचारियों ने जताया आभार

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने केन्द्र प्रवर्तित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में तीन महीनों की कार्यवृद्धि की है। इससे मिशन की गतिविधियों को दिसम्बर-2024 तक संचालित किया जा सकेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य शहरी विकास अभिकरण को परिपत्र जारी किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को तीन महीनों (1 अक्टूबर-2024 से 31 दिसम्बर-2024 तक) की कार्यवृद्धि प्रदान किए जाने पर राज्य मिशन प्रबंधन इकाई में कार्यरत राज्य मिशन प्रबंधक तथा सिटी मिशन प्रबंधन इकाईयों में कार्यरत सिटी मिशन प्रबंधकों, सामुदायिक संगठकों और सीआरपी महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव से आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर आभार प्रकट किया है। राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में कार्यवृद्धि से प्रदेश के 170 नगरीय निकायों में कार्यरत सिटी मिशन प्रबंधकों, सामुदायिक संगठकों, स्वसहायता समूहों, सीआरपी की महिलाओं एवं राज्य कार्यालय में कार्यरत राज्य मिशन प्रबंधकों को दिसम्बर-2024 तक नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

पांचवी, आठवीं की परीक्षा को बोर्ड करने से शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी?

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार के पांचवी, आठवीं की परीक्षा को बोर्ड कर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने फैसले को हास्यपद बताया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी है, सुविधाओं का अभाव है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां चाक, डस्टर और बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सिर्फ परीक्षा को बोर्ड करने से शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने ही तो पांचवी, आठवीं को बोर्ड परीक्षा से बाहर किया था? प्रदेश में शिक्षा का बाजारीकरण किया था। बिना सुविधा के निजी स्कूल खोलने की अनुमति दी थी। 3000 से अधिक स्कूलों को बंद कर 22 हजार से अधिक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के पद को समाप्त किया था। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 33,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर मुहर लगनी चाहिए थी। प्रदेश के स्कूलों में रिक्त 57,000 से अधिक शिक्षकों के पद को भरने का फैसला होना था। आज प्रदेश में कई ऐसे स्कूल है जो शिक्षक विहीन है, कई स्कूलों में एक शिक्षक है, कई स्कूलों में दो शिक्षक है, कहीं पर विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है, जब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाएगा.

भाजपा सरकार की उपेक्षा से किसान मायूस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदनियती के चलते छत्तीसगढ़ के धान बेचने वाले किसान मायूस हैं। प्रदेश के अधिकांश समिति और धान संग्रहण केंद्र बारदानों की कमी से जूझ रहे हैं। यह सरकार न पर्याप्त मात्रा में नए बारदाना खरीद पाई है और ना ही राइस मिलरों से बारदाना उपलब्ध कराने का समुचित प्रयास हुआ है, पीडीएस के बारदाने तक समुचित मात्रा में यह सरकार कलेक्ट नहीं कर पाई है जिसके चलते किसान भटकने मजबूर हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि ऑनलाइन टोकन ऐप खुलते ही 10 से 15 मिनट में तय लिमिट खत्म हो जा रही है। समितियों में किसानों को मैन्युअल टोकन नहीं मिल पा रहा है जो 60-40 का रेशियो ऑनलाईन और सोसायिटीयों से टोकन जारी करने में तय किया गया है उसका पालन कहीं पर नहीं हो पा रहा है अधिकांश समितियों में दिसंबर के पहले हफ्ते से लेकर 15 दिसंबर तक के टोकन खत्म हो चुके हैं किसानों को टोकन के अभाव में मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। भाजपा सरकार की अकर्मण्यता के चलते किसानों को अपनी उपज की सुरक्षा के लिए कड़ी ठंड में किसानों को पहरेदारी करना पड़ रहा है।

ऑक्सीजन की कमी नवजात की मौत सरकार के माथे पर कलंक

रायपुर। भाजपा सरकार की अकर्मण्यता के कारण राज्य की स्वास्थ्य सुविधा बदतर हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य के कोरबा जिले में एक ही दिन में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण एक प्रसूता ओर उसके जुड़वा बच्चों की मौत हो गयी है। इसी दिन एक संरक्षित जनजाति की महिला ने एम्बुलेंस में शिशु को जन्म दिया लेकिन एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उसके नवजात शिशु की मौत हो गयी। यह घटनाएं सरकार के माथे पर कलंक है तथा राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सुविधा का आईना है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी के मेकाहारा से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र तक स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे है। भाजपा सरकार की दुर्भावना, उपेक्षा और निकम्मेपन के चलते हैं मामूली बीमारी से बड़ी संख्या में लोग बे-मौत मरने मजबूर हैं। पीलिया, मलेरिया, डायरिया से रोज़ मौत हो रही है। सुकमा के गोगुंडा गांव में 15 दिनों में 10 आदिवासियों की मलेरिया से मौत हो गयी है। मौसमी बीमारियों से रोकथाम के उपाय बंद होने के कारण विगत 11 महीनों में ही प्रदेश में मलेरिया संक्रमण दर 8 गुना बढ़ गई है। हमर अस्पताल, हाट बाजार क्लीनिक, मोहल्ला क्लीनिक, शहरी स्लम चिकित्सक सेवा कार्यक्रम बाधित है।

शराब पिलाकर गैंगरेप करने वाले 3 गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी के मुजगहन में पुलिस ने महिला को शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

ये तीनों आरोपी मुजगहन क्षेत्र के कांदुल ग्राम के रहने वाले है। तीनों ने महिला को फोन कर बुलाया और उसके साथ शराब पी, इन्होने फिर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना 25 नवंबर की बताई जा रही है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि, 25 नवंबर की शाम 5.30 बजे पीडिता के पूर्व परिचित मित्र के माध्यम से आरोपी प्रेमलाल साहू के साथ उसकी जान पहचान हुई थी। इस दौरान आरोपी प्रेमलाल साहू ने फोन कर उसे अपने घर बुलाया। जिसके बाद पीड़िता अपनी स्कुटी से आरोपी के बुलाये पते पर पहुंची। जहां उसने अपनी गाडी को दूसरे जगह रखकर तीनों आरोपियों के साथ उनके आटो में बैठकर उनके द्वारा बताये गये जगह पर पहुंची। जहां तीनों आरोपियो के साथ उसने शराब का सेवन किया। नशा होने पर आरोपियों ने पीडिता के साथ जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले गिरफ्तार आरोपी हैं- 1. राजू उर्फ राजीव साहू पिता स्व. धनुष साहू उम्र 21 साल 2. प्रेमलाल साहू पिता शिवप्रसाद साहू उम्र 29 साल 3. धनेश्वर निषाद पिता बोधीराम निषाद उम्र 33 साल

डॉ. चंदेल आईसीएआर प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम समिति के सदस्य मनोनीत

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल को देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विश्वविद्यालयीन प्रवेश परीक्षा 2025 की पाठ्यक्रम निर्धारण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह समिति देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों हेतु स्नातक स्तरीय प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी। यह समिति विभिन्न राज्य शिक्षा मण्डलों द्वारा पढ़ाये जाने वाले कृषि पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर उनके मध्य एकरूपता लाने का कार्य करेगी। समिति द्वारा कृषि के साथ विज्ञान के विभिन्न विषयों के मध्य भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपमहानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. आर.सी. अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति में डॉ. चंदेल सहित कुल 8 सदस्य रखे गये हैं। डॉ. चंदेल का आई.सी.ए.आर. प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम समिति में मनोनय छत्तीसगढ़ के गौरव का विषय है।

जापान के औद्योगिक समूह के साथ हुआ अनुबंध

कृषि विवि के स्टार्टअप के उत्पाद जापान और अन्य एशियाई देशों में बिकेंगे

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेन्टर, (राबी) के स्टार्टअप ''उर्वरक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड'' एवं ''कोनोइके ग्रुप, जापान'' के बीच आज यहां एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की उपस्थिति में उर्वरक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक अनिल पासरी एवं कोनोइके ग्रुप के महाप्रबंधक कात्सुफुमि ओत्सुकी ने एम.ओ.यू. में हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर कोनोइके ग्रुप सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट

मैनेजर हीरोशी सोएजिमा, कार्यकारी अधिकारी तोशिहिरो फुजिवारा और उनकी टीम सहित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक एवं निदेशकगण तथा कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता एवं एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेन्टर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. हुलास पाठक एवं उद्योगपति उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि इस अनुबंध के तहत छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप ''उर्वरक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड'' द्वारा उत्पादित ''सॉइल कंडीशनर'' एवं अन्य उत्पादों को जापान और अन्य उपमहाद्वीपों के देशों में विक्रय किया जा सकेगा। उर्वरक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्टील स्लैग से एक अभिनव उत्पाद, सॉइल कंडीशनर विकसित किया है, जिसमें 13 प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। यह उत्पाद फसल उत्पादन में वृद्धि करता है और किसानों की आय को बढ़ाता है।

एमओयू समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने स्टार्टअप को बधाई दी और जापानी प्रतिनिधियों के साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्टार्टअप इकोसिस्टम को साझा किया। उन्होंने भविष्य में और अन्य स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी करने का स्वागत किया, ताकि वैश्विक स्तर पर विकास हो सके। कोनोइके ग्रुप के महाप्रबंधक कात्सुफुमि ओत्सुकी ने अपने संबोधन में अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी और जापान में इस उत्पाद को बाजार में लाने की रणनीतियों पर चर्चा की।

उन्होंने जापान की औद्योगिक संस्कृति और वहां के औद्योगिक क्षेत्र के जीडीपी में योगदान के बारे में बताया। इस अवसर पर आई.जी.के.वी. राबी, रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. हुलास पाठक ने स्टार्टअप को बधाई दी और सभी गणमान्य अतिथियों को संबोधित किया। उन्होंने कृषि व्यवसाय में नवाचार को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में इसके योगदान में इनक्यूबेशन केंद्र की भूमिका को रेखांकित किया।

अब सड़कों के बाधित ट्रैफिक से छुटकारा दिलाने मार्ग के किनारे खड़ी वाहनों और अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई

रायपुर। रायपुर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक बाधित करने वाले सड़क किनारे खड़े वाहनों एवं ठेलों पर अब कार्रवाई होगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई है। यह टीम सड़कों के किनारे खड़ी वाहनों और अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगी। आज से शुरू हुए कार्रवाई में पुलिस ने दो ऑटो को जब्त किया है। वहीं नगर निगम की टीम ने 4 ठेलों को अंबेडकर चौक के पास से जब्त किया है। साथ ही अन्य वाहन चालकों को समझाइश भी दी गई। जिन-जिन स्थानों पर अवैध तरीके से पार्किंग होने पर यातायात बाधित

हो रहा है, उन स्थानों पर भी कार्रवाई की गई है।

सड़कों के किनारे वाहन खड़ी होने और अतिक्रमण होने की वजह से सड़कें सकरी हो रही है। इस वजह से सुबह और शाम के समय में शहर में यातायात बाधित हो रहा है। इस यातायात बाधित होने की वजह से जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है। साथ ही जहां बड़े-बड़े बेसमेंट में पार्किंग पर अवैध तरीके से गोदाम बनाया गया है, उन पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है जैसे नयापारा चैक इत्यादि। साथ ही गोदाम में कचरा फैलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिन सड़कों से आगे बढ़ाकर होर्डिंग्स लगाई गई है, उसे भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शहर के उन स्थानों भीड़-भाड़ हो वहां से अवैध ठेलों की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सड़कों के किनारे खड़ी कंडम गाड़ियों की भी जब्ती की जाएगी। एसएसपी संतोष सिंह एवं नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.